● वर्ष : 17 ● अंक : 132 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

रविवार 01 मार्च 2026

मुस्लिम लीग की नफरत से हुआ देश का विभाजन, कांग्रेस भी उसी राह पर: मोदी

पीएम मोदी ने अजमेर में युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे

एजेंसी। अजमेर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि जिस तरह मुस्लिम लीग की भारत के प्रति नफरत ने देश का विभाजन कराया था, उसी तरह आज कांग्रेस देश को बदनाम करने और कमजोर करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के 'शर्टलेस प्रदर्शन' को देश की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। प्रधानमंत्री प्रदेश को 16,680 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए थे और उन्होंने भारत की उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन कांग्रेस ने विदेशी मेहमानों के सामने 'ड्रामा' कर देश को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हार से निराश कांग्रेस देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने माओवादियों पर भी संविधान और लोकतंत्र से घृणा करने का आरोप लगाते हुए कहा, "इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और उसी कारण देश का विभाजन हुआ। आज कांग्रेस भी वैसा ही व्यवहार कर रही है।" प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को 'एमएमसी—मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस' करार देते हुए आरोप लगाया कि वह संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पर सशस्त्र बलों को कमजोर करने और रक्षा सौदों में घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय रक्षा सौदों में बड़े घोटाले हुए और सैनिकों को 'वन रैंक वन पेंशन' का लाभ वर्षों तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों के सम्मान और सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया इजराइल दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां आज भी राजस्थान के वीर मेजर दलपत सिंह के शौर्य को गर्व से याद किया जाता है। उन्होंने इजराइल की संसद में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलने की बात कही और हाइफा की मुक्ति में राजस्थान के सैनिकों की भूमिका का स्मरण किया। उन्होंने अजमेर को आस्था और शौर्य की भूमि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार ने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं और राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर है। शहरी विकास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना से जुड़ी लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं राज्य की जनता की सुविधा बढ़ाएंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने अजमेर-पुष्कर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार की खबरें आती थीं, लेकिन अब इस पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से राष्ट्रीय विकास का संकल्प दोहराया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि देश विज्ञान और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस शोध, नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा की उस भावना का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह दिन महान वैज्ञानिक सी. वी. रमन द्वारा किए गए ऐतिहासिक 'रमन प्रभाव' की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस खोज ने भारतीय अनुसंधान को वैश्विक पहचान दिलाई और देश को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाने, शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्रीय विकास और विश्व कल्याण के लिए करने के संकल्प को दोहराया।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

दम है, तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाएं, मोदी

सीबीआई के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज का निर्णय दिया है। निर्णय में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में आबकारी नीति घोटाले के मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, बिना सबूत के आरोपियों को आपराधिक मुकदमे में घसीटना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आपराधिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल जांच एजेंसी द्वारा किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, न्यायिक जांच की कसौटी पर अभियोजन पक्ष जरा भी नहीं टिक पाया। कोर्ट ने आरोपियों को फंसाने के लिए व्यापक साजिश के दावे की पुष्टि की है। जो सीबीआई के लिए सबसे बड़ा झटका है। अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को पूर्व नियोजित और कोरियोग्राफड बताते हुए गंभीर टिप्पणी की है।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा, आपराधिक मुकदमे में इस तरह से किसी को भी नहीं उलझा सकते हैं। राजनीतिक असहमति को आपराधिक मामलों के रूप में प्रस्तुत करने की कोर्ट ने तीव्र आलोचना फैसले में की है। उल्लेखनीय है, जांच एजेंसी ने साउथ लावी के नाम से तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी कविता को 165 दिन तक हिरासत में रखा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अकारण 181 दिनों तक जेल में बंद करके रखा गया था। इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने फैसले में उत्तर और दक्षिण के बीच में राजनीतिक विद्वेष फैलाने का कृत्य माना है। न्यायालय ने आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह को आरोपी नंबर एक बनाने पर कड़ी आपत्ति फैसले में दर्ज की है।

सीबीआई ने जिस तरह से आबकारी नीति को जबरिया अपराध साबित करने के लिए एक के बाद एक कई लोगों को फंसाती चली गई। संदिग्ध गवाह बनाए गए। काल्पनिक सबूत बयान के आधार पर तैयार करने की कोशिश की गई। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई के अधिकारियों ने जांच करते हुए चुनाव प्रचार, होटल बुकिंग, और भुगतान इत्यादि की जांच की। चुनाव आयोग के अधिकारों का उपयोग सीबीआई ने किया है। अधिकारियों ने संविधानिक सीमाओं को पार किया है। जिन लोगों ने पैसे लेने और देने के आरोप स्वीकार किए थे। सीबीआई ने उन्हें गवाह बना लिया। उन गवाहों के बयान पर अन्य लोगों को फंसाया गया। अदालत ने फैसले में कहा अभियोजन के बयान की कॉपी अदालत को नहीं मिली। रिकॉर्ड को देखने से पता लगता है, जांच एजेंसी ने अदालत को भी दृग भ्रमित किया है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

इजरायल ने किया ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान में धमाके से अफरा-तफरी, तनाव बढ़ा

तेल अवीव। मध्य पूर्व की गंभीर तनावपूर्ण स्थिति अब और भी भयावह होती नजर आ रही है, खासतौर पर तब जबकि इजरायल ने ईरान पर प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह इस हमले की आधिकारिक पुष्टि की है और देशभर में राज्य आपातकाल की घोषणा की है। इस हमले के बाद तेहरान सहित कई इलाकों से जोरदार धमाकों की आवाजें और आसमान में धुएँ के गुबार की तस्वीरें सामने आई हैं। इज़राइल ने अपनी सेना द्वारा जारी बयान में कहा है, कि यह कार्रवाई संभावित खतरे को पहले से रोकने के उद्देश्य से की गई है। इसी आशंका को देखते हुए इजरायली सेना ने अपने नागरिकों के लिए "प्रोएक्टिव अलर्ट" जारी करते हुए पूरे देश में सायरन बजाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। आईएसएफ (इज़रायल डिफेंस फोर्सेस) के आदेश पर जनता को शरणस्थलों में जाने व आवश्यक सावधानियाँ बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित रहें। सायरन की गूँज से तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में भी तनाव का माहौल देखने को मिला है।

भारत ने इजरायल में अपने नागरिकों के लिए जारी किया परामर्श, सावधानी बरतने की अपील

नई दिल्ली। इजरायल-ईरान तनाव के बीच भारत ने इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने की अपील की है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को जारी परामर्श में कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। एडवाइजरी में भारतीयों से अपने निवास या कार्यस्थल के निकटतम सुरक्षित आश्रय स्थलों की जानकारी रखने और उनके पास रहने को कहा गया है। अगली सूचना तक गैर-आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही स्थानीय समाचार, आधिकारिक घोषणाओं और आपातकालीन अलर्ट पर नजर रखने को कहा गया है। दूतावास ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक 24 घंटे हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दूतावास संबंधित इजरायली अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में है और आवश्यकतानुसार अपडेट जारी करेगा। यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। तेहरान सहित कई शहरों में विस्फोटों की खबरें हैं। इजरायल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और देशभर में आपातकाल घोषित किया गया है।

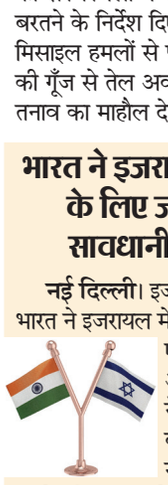

सीबीआई ने आयुध निर्माणी सेवा अधिकारी के ठिकानों की ली तलाशी, लगभग 55 लाख रुपये के गहने और नकदी जब्त

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस) के अधिकारी अमित सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर शुक्रवार को पांच परिसरों पर तलाशी ली। तलाशी में 49 लाख रुपये के आभूषण, 5 लाख रुपये नकद तथा संपत्ति संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए। सीबीआई के अनुसार, अमित सिंह बैच 1998 के अधिकारी हैं। वह वर्ष 2022 से 2025 के दौरान हजरतपुर, फिरोजाबाद स्थित आयुध उपकरण निर्माणी हजरतपुर में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती कानपुर स्थित ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड प्रशिक्षण अकादमी में है। एजेंसी ने बताया कि उनके खिलाफ 26 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में उन्होंने अपनी ज्ञात आय से 55.58 लाख रुपये अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय से 73.28 प्रतिशत अधिक है। मामला दर्ज करने के बाद सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किए गए। 27 फरवरी को आगरा, लखनऊ, बरेली और कानपुर स्थित पांच आवासीय एवं कार्यालय परिसरों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक, ऋणपत्र, क्रेडिट कार्ड तथा वाहन संबंधी अभिलेख बरामद किए गए। जांच में आगरा, लखनऊ और बरेली में तीन आवासीय संपत्तियों का विवरण मिला। आगरा स्थित फ्लैट वर्ष 2025 में तथा लखनऊ स्थित फ्लैट वर्ष 2023 में क्रय किया गया था।

डीयू के दीक्षांत में 1.20 लाख छात्रों को प्रदान की गयी डिग्रियां, उपराष्ट्रपति ने दिया राष्ट्र प्रथम का मंत्र

एजेंसी। नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में 1,20,408 विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्रियां प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने युवाओं से "राष्ट्र प्रथम" को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय खेल परिसर में आयोजित समारोह में 734 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई, जबकि 132 गोल्ड और सिल्वर मेडल तथा पुरस्कार वितरित किए गए। उपराष्ट्रपति ने 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मेडल प्रदान किए और 'बुक ऑफ हाइलाइट्स' का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की 104 वर्ष लंबी गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1922 में मात्र तीन कॉलेज, दो संकाय, आठ विभाग और 750 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ यह संस्थान आज 16 संकायों, 86 विभागों, 90 कॉलेजों, 20 हॉल एवं छात्रावासों, 30 से अधिक केंद्रों एवं संस्थानों, 34 पुस्तकालयों और छह लाख से अधिक विद्यार्थियों के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। उन्होंने विश्वविद्यालय की निरंतर बेहतर होती राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय विश्व के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में और ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत केवल औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण की पूर्णता और दूसरे चरण की शुरुआत है। आज के स्नातक ऐसे समय में नई जिम्मेदारियों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जब प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक लोकतांत्रिक चुनौतियां विश्व व्यवस्था को बदल रही हैं। उन्होंने कहा, "डिग्री केवल सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने कौशल का उपयोग करने और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने की प्रतिबद्धता है।

एयर इंडिया की तेल अवीव जा रही उड़ान बीच रास्ते से मुंबई डायवर्ट

नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने शनिवार को अपनी नई दिल्ली-तेल अवीव फ्लाइट को इजरायली हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से बीच रास्ते से मुंबई के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिसके बाद कुछ हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "28 फरवरी को नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए संचालित फ्लाइट संख्या एआई-139 इजराइल में हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्री एवं चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भारत लौट रही है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट नई दिल्ली से तेल अवीव को जा रही थी। एयर इंडिया ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव का हवाला देते हुए एक मार्च से एक हफ्ते के लिए इजराइल के लिए उड़ानें रोक दी हैं। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लाइट संख्या एआई-139 को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया है। कंपनी ने कहा, "हम अपने फ्लाइट संचालन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी माहौल का आकलन करते रहेंगे और जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन को पहले से एडजस्ट करेंगे।

नोटों से भरा विमान हुआ क्रैश-15 की मौत, वहीं पैसे बटोरने वालों की लगी भीड़, मची अफरा तफरी

पाज़। बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी ला पाज़ के निकटवर्ती शहर एल ऑल्टो में शुक्रवार शाम एक बड़ा विमान हादसा हो गया जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद एक अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हो गई जब विमान में रखे करोड़ों के नए नोट पूरी सड़क पर बिखर गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मलबे और धुएं के बीच सैकड़ों लोग बचाव कार्यों में मदद करने के बजाय बिखरी हुई नकदी को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन को लोगों को हटाने के लिए वॉटर कैनन और दंगा नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। बोलीविया के सेंट्रल बैंक ने पुष्टि की है कि विमान नए बैंक नोटों को देश के आंतरिक हिस्सों में ले जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान ने एल ऑल्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण वह अनियंत्रित होकर पास की मुख्य सड़क पर जा गिरा। सड़क पर गिरते ही विमान ने करीब एक दर्जन से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।

मतदाता सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी कहा- बेमतलब के बहानेबाजी ठीक नहीं

एजेंसी। नई दिल्ली

देश की सर्वोच्च अदालत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अस्पष्ट और अप्रासंगिक कारणों के साथ बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाकर प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश न करे। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि हर दिन कोई न कोई बेमतलब का बहाना बनाकर न्यायिक प्रक्रिया में देरी करने का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है, जो मूल रूप से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का कार्य है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी उन न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैनात किया गया था। सिब्बल का तर्क था कि आयोग के अधिकारी यह तय कर रहे हैं कि मतदाताओं के दावों के साथ कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने निर्देश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि तौर-तरीके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे।

हालांकि, पीठ ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उनका तात्पर्य केवल यह था कि वह यह तय करेंगे कि किस अधिकारी की तैनाती कहां होगी और उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। दावों के निपटान और दस्तावेजों की वैधता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल तैनात न्यायिक अधिकारियों के पास ही सुरक्षित है।

एआई-आधारित टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से भारतीय स्कूलों के बच्चों की प्राइवेसी खतरे में?

एजेंसी। नई दिल्ली

शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रसार जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़े जोखिम भी सामने आ रहे हैं। अब चर्चा बच्चों की सुरक्षा, उनकी निजता और अधिकारों पर मंडरा रहे खतरों तक होने लगी है। दुनिया भर में एआई-आधारित टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच स्कूलों में बच्चों के डेटा के संभावित दुरुपयोग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएनआरसी, यूनेस्को, यूएनआईसीआरआई और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय समेत विभिन्न यूएन विभागों ने एक संयुक्त बयान जारी कर बच्चों के डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी पर कड़े नियमों की जरुरत पर जोर दिया है। एआई के इस्तेमाल से डेटा लीक के गंभीर खतरे पहले ही कई बार उजागर हो चुके हैं। 2025 में अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक स्कूल पर बड़े साइबर हमले और डेटा ब्रीच को लेकर मुकदमा दायर किया गया था। आरोप है कि इस घटना में 6 करोड़ से ज्यादा छात्रों और एक करोड़ शिक्षकों की संवेदनशील जानकारियां लीक हो गईं, जिनमें सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे बेहद निजी विवरण भी शामिल थे। यह स्कूल एक प्रमुख स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो व्यापक पैमाने पर स्कूली डेटा संभालता है। भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। हाल ही में की गई एक पायलट स्टडी के मुताबिक भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को सिर्फ नौ महीनों में दो लाख से ज्यादा साइबर हमलों और लगभग चार लाख डेटा ब्रीच की घटनाओं का सामना करना पड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि देश में स्कूली डेटा कितनी बड़ी मात्रा में साइबर अपराधियों के निशाने पर है। फरवरी 2026 में जारी किया गया उनका पहला प्रोडक्ट 'एनीटाइम टेस्टिंग मशीन (एटीएम)' इसी तकनीक से संचालित है। यह टूल करिकुलम आधारित टेस्ट बनाता है, बच्चों के हस्तलिखित उत्तरों को डिजिटाइज करता है, क्लॉड की मदद से ग्रेडिंग करता है और द्विभाषी पर्सनलाइज्ड फीडबैक प्रदान करता है।

बच्चों के डेटा के संभावित दुरुपयोग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने जताई चिंता

केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर खुश अन्ना हजारे, लेकिन दे दी बड़ी सीख

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को आबकारी नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे मामले में दोनों नेताओं और 21 अन्य को बरी किया। इस फसले पर सामजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी खुशी जाहिर की है। अन्ना हजारे ने कहा, हमारा देश अपनी न्यायिक और सुरक्षा प्रणालियों की ताकत पर चलता है। विविध दलों, जातियों, धर्मों और समुदायों वाला इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद, न्यायपालिका के कारण ही सुचारू रूप से चलता है। इसके बिना अराजकता और अशांति फैलेगी। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुनाकर कहा है कि केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तब इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। अन्ना ने कहा, मैंने पहले केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा था, वह न्याय व्यवस्था का निर्णय नहीं था।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

मानसून में नहीं होगी जलभराव की स्थिति, निगम प्रशासन पहले कर रहा है तैयारी : महापौर

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राजधानी में नालों की सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा निर्धारित समय-सीमा से पूर्व सभी नालों की सफाई पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन मॉनसून से पहले व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महापौर राजा इकबाल सिंह ने शनिवार को महापौर कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि एमसीड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चार फुट से कम गहराई वाले कुल 12,892 नाले हैं, जिनकी कुल लंबाई 6,069.88 किलोमीटर है। जनवरी से अब तक इन नालों से 8,047 मैट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन नालों की नियमित रूप से सफ़ाई की जाती है और गाद निकालने का कार्य निगम द्वारा सतत रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि चार फुट से अधिक गहराई वाले कुल 800 नाले निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनकी कुल लंबाई 530.82 किलोमीटर है। जनवरी से अब तक इन बड़े नालों से 16,966 मैट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। महापौर ने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, ताकि वर्षा के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनी रहे। महापौर राजा इकबाल सिंह ने आगे बताया कि बड़े नालों की सफाई हेतु दिल्ली नगर निगम ने निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही इन नालों से गाद निकालने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समय से पूर्व पूर्ण किए जाएं और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न रहे। महापौर ने कहा कि जलभराव वाले संवेदनशील स्थानों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी और जरूरत के अनुसार पंप की व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसे स्थानों पर जलभराव होने से रोका जा सके। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में "ट्रिपल इंजन" की सरकार नागरिकों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। एमसीडी, प्रदेश सरकार के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर कार्य कर रही है, ताकि राजधानी को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दिशा में दिल्ली सरकार से हर संभव सहयोग प्राप्त हो रहा है और संयुक्त प्रयासों से दिल्ली को स्वच्छता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। महापौर ने नागरिकों से भी अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें और नालों में कूड़ा-कचरा न डालें, ताकि जल निकासी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे।

राहुल गांधी ने ईरान-इज़रायल संघर्ष पर जताई चिंता, भारतीयों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ईरान-इजरायल संघर्ष को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार के लिए हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ती शत्रुता बेहद चिंताजनक है। पश्चिम एशिया में रह रहे प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय किए जाएं।

नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉकों में कुशल शासन को आगे बढ़ाने पर फ्रंटियर 50 कार्यशाला का किया आयोजन

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। नीति आयोग ने 27 फरवरी को आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम (एडीपी/एबीपी) के तहत फ्रंटियर 50 कार्यशाला का आयोजन किया। यह सार्वजनिक नीति में डिजिटल शासन से कुशल एआई-सक्षम शासन की ओर एक रणनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। नीति आयोग ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि इस कार्यशाला में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निधि छिब्बर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर, नीति फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की विशिष्ट फेलो और मुख्य वास्तुकार देबजानी घोष और नीति आयोग के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के रोहित कुमार उपस्थित थे। मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला मजिस्ट्रेटों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। विचार-विमर्श में 50 आकांक्षी ब्लॉकों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को वास्तविक दुनिया के प्रभाव के परीक्षण क्षेत्रों के रूप में कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला के दौरान एडीपी/एबीपी न्यूज़लेटर 'आकांक्षी टाइम्स' का विमोचन किया गया। नीति आयोग के मुताबिक कार्यशाला वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय तकनीकी लाभ को प्राप्त करने, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को गति देने और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर, नीति आयोग ने सूक्ष्म स्थानीयकरण, अंतरसंचालनीय जिला डेटा स्टैक, मापने योग्य परिणामों और जवाबदेह नेतृत्व पर बल दिया।

स्कूलों में बच्चों को सुबह मिले पौष्टिक भोजन, सरकार करेगी सुनिश्चित : रेखा गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अक्षय पात्र फाउंडेशन के 'सुबह के पोषण कार्यक्रम' के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि दिल्ली में बच्चों के लिए सुबह के पोषण अभियान की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली सरकार अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल पहुंचने पर बच्चों को सुबह पौष्टिक भोजन मिले। उन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय और ऊर्जावान रहें ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, जिसके लिए उनका आहार और पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिल्ली में 6 वर्षों की निरंतर सेवा और 'सुबह के पोषण कार्यक्रम' के शुभारंभ के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पुनीत प्रयास में पूर्ण सहयोग के साथ आपके साथ दृढ़ता से खड़ी है। सेवा का यह संकल्प निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और पोषण अभियान ने देश में पोषण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। आज हर बच्चे के स्वस्थ भविष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह संकल्प केवल योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सशक्त निर्माण की मजबूत आधारशिला है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतर्षभ दास, उपाध्यक्ष चंचलपति दास, दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा उपस्थित रहे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के 'सुबह के पोषण कार्यक्रम' की दिल्ली में शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया है। यह एक पूरक पोषण पहल है जिसे स्कूली शिक्षा के शुरुआती घंटों में पोषण की गंभीर कमी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां एक पौष्टिक दोपहर का भोजन दिनभर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं एक पौष्टिक शुरुआत बच्चे के मन और शरीर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर सुबह, कई बच्चे ठीक से नाश्ता किए बिना स्कूल आते हैं। नतीजतन, सुबह के शुरुआती घंटों में उनमें ऊर्जा की कमी होती है, जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता प्रभावित होती है और कक्षा में उनका ध्यान कम हो जाता है। लंबे समय में, इससे सीखने में कमी आ सकती है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत सरकार की प्रमुख पीएम पोषण पहल (मध्य-दिन भोजन योजना) कक्षा में लंबे समय से चली आ रही भूख और कुपोषण की समस्या का समाधान करती है, लेकिन बच्चों के स्कूल आने और दोपहर के भोजन के बीच का समय उनकी पढ़ाई और एकाग्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोटीन से भरपूर तैयार नाश्ते उपलब्ध कराकर इस कमी को सीधे तौर पर दूर करता है। दोपहर का भोजन बच्चे की दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों का लगभग 35-40 प्रतिशत पूरा करता है। इसमें सुबह के पोषण को भी शामिल कर लें, तो यह बढ़कर 60-65 प्रतिशत हो जाता है। इस कार्यक्रम के दोहरे लाभ हैं: पहला, बच्चों के समय पर स्कूल पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कक्षाओं के दौरान उनका ध्यान भटकने या थकान महसूस होने की संभावना कम हो जाती है। संक्षेप में कहें तो, सुबह का पोषण कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के हमारे सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, 'पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह के घंटे संज्ञानात्मक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण विषयों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उत्पादक हो सकते हैं। महज छह महीनों में अक्षय पात्र ने पूरे देश में स्कूली बच्चों को 4 करोड़ से अधिक सुबह के ऊर्जावर्धक नाश्ते परोसे हैं। उनका लक्ष्य प्रति वर्ष 2 करोड़ नाश्ते परोसना है। मध्याह्न भोजन के लिए हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे, यानी 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 78 स्थानों पर फैले 23,000 से अधिक स्कूलों में रसोई के नेटवर्क का लाभ उठाकर, हम मध्याह्न भोजन लाभार्थियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के ये नाश्ते उपलब्ध करा सकते हैं।

जमाअत के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका -इज़राइल के संयुक्त हमले की निंदा की, भयानक क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के प्रति सावधान किया

लोकतंत्र की शान, संवाददाता सना खान

नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के कथित संयुक्त सैन्य हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे एक गंभीर और खतरनाक पहल बताया है जिससे पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को खतरा है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के अध्यक्ष ने कहा, "ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमले देश की सम्प्रभुता का गंभीर उल्लंघन हैं और एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के लिए लापरवाह कदम है। ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से ही बहुत ज़्यादा अस्थिरता और इंसानी मुश्किलों से गुज़र रहा है, ऐसे जोखिम भरे सैन्य कार्य से सिर्फ़ तनाव बढ़ेगा और आम लोगों की तकलीफ़ बढ़ेगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम या सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर झगड़े बातचीत और कूटनीति से हल होने चाहिए न कि मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से। हमले का रास्ता अंतरराष्ट्रीय कानून को कमज़ोर करता है और शांति बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार ग्लोबल संस्थाओं की अथॉरिटी को कमज़ोर करता है।" सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि इस इलाके में इज़राइल की बार-बार की सैन्य कार्रवाई, जो अब ईरान पर सीधे हमले तक बढ़ गई है, टकराव के एक ऐसे पैटर्न को प्रदर्शित करती है जो पश्चिम एशिया को अस्थिर करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बातचीत को बढ़ावा देने के बजाय सैन्य कार्रवाई का समर्थन करना चुना है जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष भड़कने का खतरा है और इसके अप्रत्याशित नतीजे निकलेंगे। उन्होंने तेहरान और दूसरे इलाकों में धमाकों, आम लोगों की ज़िंदगी में रुकावटों और बदले की कार्रवाई की संभावना पर गहरी चिंता जताई, जिससे कई देशों में लाखों लोगों को खतरा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस इलाके में युद्धों की वजह से पहले भी बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत हुई है, लोग बेघर हुए हैं, आर्थिक दिक्कतें आई हैं और लंबे समय तक अस्थिरता रही है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे सभी पक्षों पर तुरंत तनाव कम करने और आपसी तालमेल बनाने के लिए दबाव डालें।

पंजाब की किसान महाचौपाल में खरगे-राहुल ने मोदी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा

लोकतंत्र की शान, संवाददाता जीशान अली

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के बरनाला में किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महाचौपाल को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को भाजपा की बी टीम करार देते हुए कहा कि ये लोग कभी किसानों या मजदूरों की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उन्होंने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि रोने-धोने से काम नहीं चलेगा। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो राहुल गांधी की तरह लड़िए। उन्होंने केजरीवाल और मोदी की कार्यशैली को एक जैसा बताते हुए उन्हें ढोंगी करार दिया। पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खरगे ने कहा कि आज गुरुओं की इस धरती पर गोलियां चल रही हैं और लोग असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सरेआम धमकियां मिल रही हैं और अमित शाह व राज्य सरकार दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर पंजाब सरकार मजबूत है, तो नशे का जाल क्यों खत्म नहीं हो रहा? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में बड़े बांध और पावर प्लांट बने, जबकि मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी हैं, जो ट्रंप के इशारों पर चलते हैं और देश के संसाधनों को बेचकर लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं।

एनएसयूआई ने "संविधान संकल्प सभा" के रूप में आयोजित किया विनोद जाखड़ का शपथ ग्रहण समारोह

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के शपथ ग्रहण समारोह को एक "संविधान संकल्प सभा" के रूप में आयोजित किया। जिसमें देशभर से आए हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत के संविधान की रक्षा और छात्र अधिकारों की सुरक्षा का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक साधारण और संघर्षशील परिवार से आने वाले कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि उन सभी परिश्रमी परिवारों के बेटों और बेटियों का है, जो संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने बेरोजगारी, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, शिक्षा के निजीकरण और छात्रसंघ चुनावों की बहाली जैसे मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करने की घोषणा की। विनोद जाखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय वैचारिक थोपने के स्थान नहीं हैं। जो शक्तियां शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित कर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना चाहती हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि विद्यार्थी संविधान के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। सभा में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने इसे छात्र आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उनका कहना था कि देश का युवा संविधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और समान अवसर की रक्षा के लिए एकजुट है। अपने संबोधन के समापन में विनोद जाखड़ ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे परिसर दर परिसर, राज्य दर राज्य। यह संघर्ष विद्यार्थियों के अधिकारों और राष्ट्र के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए है। इस अवसर पर समारोह में सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, संजना जाटव, एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार, एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, अंशुल त्रिवेदी और नीरज कुंदन सहित कई प्रमुख नेताओं और अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, छात्र प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी उपस्थिति रहे।

दिल्ली पुलिस: बाइक चोरी का खेल खत्म: थाना पहाड़गंज, मध्य जिला की टीम ने ऑटो लिफ्टर को दबोचा-चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार चोरी की मोटरसाइकिल बरामद थाना पहाड़गंज टीम की त्वरित कार्रवाई तकनीकी निगरानी एवं सीसीटीवी विश्लेषण की अहम भूमिका **घटना का संक्षिप्त विवरण:** दिनांक 25.01.2026 को थाना पहाड़गंज में ई-एफआईआर संख्या 001962/26, धारा 305(बी) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल, जो बसंत रोड स्थित राहुल गेस्ट हाउस, पहाड़गंज, दिल्ली के पास खड़ी थी, चोरी हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी हुए वाहन की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तुरंत प्रयास शुरू किए गए।

टीम एवं कार्रवाई: एसएचओ/थाना पहाड़गंज के पर्यवेक्षण में एएसआई राकेश, हेड कांस्टेबल जगवीर, कांस्टेबल दीपक तथा कांस्टेबल पुनीत की एक समर्पित टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल तथा आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की। स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया तथा गुप्त सूचनादाताओं को लगाया गया। तकनीकी निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों का मैनुअल सत्यापन भी किया गया। लगातार प्रयासों और सतत निगरानी के बाद दिनांक 14.02.2026 को विशेष गुप्त सूचना के आधार पर रोहित @ देव, निवासी एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, आयु 26 वर्ष, को मोतिया खान चौक, सदर थाना रोड, दिल्ली के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई।

आगे की पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

गिरफ्तार आरोपी: रोहित @ देव, निवासी एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, आयु 26 वर्ष

पूर्व आपराधिक संलिप्तता: एफआईआर संख्या 64/24, धारा 304(2) बीएनएस, थाना नॉर्थ एवेन्यू ई-एफआईआर संख्या 80110710/24, धारा 303(2) बीएनएस, थाना मंदिर मार्ग

बरामदगी: एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद,(अनंत मित्तल), आईपीएस,उपायुक्त पुलिस,मध्य जिला, नई दिल्ली

बीएसएल का "ग्लोबल आउटरीच समिट-2.0" 28 अप्रैल से नई दिल्ली में

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स एसोसिएशन (बीएसएल) ने तीन दिवसीय "ग्लोबल आउटरीच समिट 2.0" की घोषणा शनिवार को की। यह अंतरराष्ट्रीय समिट 28 से 30 अप्रैल तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित होगी। बीएसएल के अध्यक्ष रमन दत्ता ने यूएस कॉम्प्लेक्स जसोला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि समिट में वैश्विक और घरेलू परिधान एवं लाइफस्टाइल ब्रांड्स, बाइंग हाउसेज के सीईओ, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, निवेशक और नीति-निर्माता एक मंच पर एकत्रित होंगे। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में मजबूत करना और संरचित व्यापार साझेदारियों को नई गति देना। उन्होंने बताया कि बीएसएल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "फार्म टू फॉरेन" विजन से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, ताकि विश्व "मेड इन इंडिया" उत्पादों को अपनाए। संगठन का लक्ष्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत के परिधान एवं टेक्सटाइल इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना है। रमन दत्ता ने बताया कि बीएसएल ने वित्त वर्ष 2026–28 के दौरान 18,000 करोड़ के व्यापार सुविधा लक्ष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया है। यह लक्ष्य उद्योग में ठोस आर्थिक परिणाम और निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्लोबल आउटरीच समिट 2.0 का उद्देश्य इरादों को क्रियान्वयन में बदलना है। इसके साथ ही भारत के परिधान और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत के बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाना है। बीएसएल के को-चेयरमैन नीरज नागपाल ने कहा कि एक ऐसा संरचित प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां भारतीय ब्रांड्स वैश्विक मंच पर आगे बढ़ें और भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत को दुनिया तक पहुंचाएं। बीएसएल के फाउंडिंग मेंबर संजय शुक्ला ने कहा कि बीएसएल की 'पंच पहल' रणनीति के तहत सस्टेनेबिलिटी, सहयोग और वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाकर अगले दो वर्षों में 2 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई गई है। अन्य वक्ताओं ने भी सस्टेनेबिलिटी, सीईओ-स्तरीय भागीदारी और वैश्विक सहयोग को इस समिट की प्रमुख विशेषताएं बताया। उन्होंने कहा कि "ग्लोबल आउटरीच समिट 2.0 " को भारत के परिधान एवं लाइफस्टाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो देश को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है।

संक्षिप्त समाचार

योगी सरकार प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में देगी आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा

लोकतंत्र की शान : लखनऊ : आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान कार्ड) के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों से एमओयू साइन करेगी। प्रदेश में कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पताल हैं। प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में पहले से ही आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जा रहा है। इसी के सफल परिणाम को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के अन्य कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

मुफ्त ओपीडी अप्वाइंटमेंट, जांच और गंभीर मरीजों को फ्री परिवहन की मिलेगी सुविधा-साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि जनवरी-26 से प्रयागराज के कैंटोनमेंट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है। वहां पर मरीजों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी आदि गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही मुफ्त ओपीडी अप्वाइंटमेंट, मुफ्त जांच एवं गंभीर मरीजों को मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जा रही है, जिसके सफल परिणाम सामने आए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के अन्य 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ एमओयू साइन किया जाएगा। इसके लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) द्वारा लगभग सभी औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। उन्होंने बताया कि एमओयू के बाद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, झांसी और बबीना के कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इन अस्पतालों के जुड़ने से प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पैनल्ड अस्पतालों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी।

विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

लोकतंत्र की शान : बिजनौर। एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को दर्जनों पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभिन्न मामलों में कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए लंबित मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि फरवरी 2025 में चांदपुर तहसील के ग्राम पुरैना में एक पूर्व सैनिक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। आरोप है कि नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार भरत विहार क्षेत्र से एक पूर्व सैनिक का पोता 24 दिसंबर 2025 से लापता है। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक की बैनामाशुदा संपत्ति पर निर्माण कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेटियों के साथ छेड़छाड़ और फब्तियां कसने की शिकायत पर भी ठोस कार्रवाई न होने की बात कही गई। नजीबाबाद के ग्राम धंसानी में पार्किंग विवाद को लेकर एक सेवारत सैनिक के साथ कथित अभद्र व्यवहार और रिश्वत मांगने की शिकायत भी ज्ञापन में शामिल है। संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व सैनिक धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।

यूपी पुलिस कर्मियों की 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां निरस्त

लोकतंत्र की शान : उन्नाव : उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक प्रदेश भर में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। इस आदेश के तहत किसी भी पुलिस कर्मी को इस अवधि में अवकाश नहीं मिलेगा, जब तक कि सक्षम उच्च अधिकारी की विशेष अनुमति न हो। जारी आदेश में डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और सभी एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान किसी भी स्तर पर अवकाश न स्वीकृत किया जाए और सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने-अपने तैनाती स्थलों पर उपस्थित रहें। पुलिस विभाग का मानना है कि होली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्योहार में भारी भीड़, पारंपरिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों के कारण संवेदनशील स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती, मोबाइल पेट्रोलिंग और 112, PRV जैसी सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करते रहने और आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। इस कदम का लक्ष्य त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की law and order चुनौती को प्रभावी ढंग से संभालना और प्रदेशवासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना बताया गया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार को भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा किसी भी असामान्य घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दो घायल

बिजनौर। किरतपुर क्षेत्र में नहटौर-किरतपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुनील (45) पुत्र बसंत सिंह निवासी ग्राम नारगदी, थाना नहटौर के रूप में हुई है। बताया गया कि सुनील अपने साथियों कपिल और कोमल के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे नहटौर-किरतपुर रोड पर पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि कपिल और कोमल का उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है।

साक्षी महाराज का तीखा हमला

लोकतंत्र की शान : उन्नाव : सांसद साक्षी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा बयान देते हुए सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती विशुद्ध रूप से कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े थे और राम मंदिर आंदोलन के दौरान संतों के साझा मंच से दूरी बनाए रखी थी।

"कांग्रेस के पिट्ठू" का आरोप-साक्षी महाराज ने कहा कि जब राम मंदिर आंदोलन के लिए अखिल भारतीय संत समिति के मंच पर देशभर के संत एकत्र हुए, तब स्वरूपानंद सरस्वती उस मंच पर नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि "जैसे गुरु थे, वैसे ही शिष्य हैं" और अविमुक्तेश्वरानंद को भी कांग्रेस समर्थक बताया।

अखिलेश यादव पर भी निशाना-समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि "अखिलेश सरकार के समय राम भक्तों और संतों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलीं। जिन हाथों ने लाशें उठाईं, वे दृश्य आज भी याद हैं।" उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि यदि राजनीति करनी है तो पहले हिंदू समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगें।

तहसील बार एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को तहसील बार एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन तहसील परिसर में किया इस अवसर पर अधिवक्ताओं और अतिथियों ने फूल एवं गुलाल की होली खेलकर भाईचारे का संदेश दिया, वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने सभी अधिवक्ताओं तथा एस डी एम हिमांशु उपाध्याय के साथ जमकर होली खेली, वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी, एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का टोपी वह फूल माला और बुके देकर स्वागत किया, समारोह में कलाकारों ने सांस्कृतिक और धार्मिक गीतों पर प्रस्तुति दी जिससे पूरा परिसर होली के पारंपरिक गीतों से गूंज उठा, अधिवक्ताओं ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाया और फूलों की वर्षा की वहीं विधायक महेंद्र सिंह ने सभी को होली के शुभकामनाएं दी, उन्होंने कहा कि होली का पर्व आपसी मतभेद बुलाकर गले मिलने का त्यौहार है विधायक ने सभी से मतभेद बुलाकर प्रेम और भाईचारे के साथ इस उत्सव को मनाने की अपील की, इस मौके पर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, महासचिव बृजकिशोर, देवेंद्र खड़कवंशी, चंद्र सेन अग्रवाल, मदन खड़कवंशी, महावीर चौहान, मुजाहिद चौधरी, महिपाल नागर, वीर सिंह प्रजापति, शिवराज सिंह राणा, मेघराज सिंह, राजीव शर्मा, सुबोध शर्मा, गंगा शरण सिंह खड़कवंशी, जय राणा और महेंद्र प्रजापति आदि सहित भारी संख्या में अधिवक्ता गढ़ मौजूद रहे।

हर्षो उल्लास के साथ 2 मार्च को हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी निकाला जाएगा होली का जुलूस

लोक तंत्र की शान, (खिज़्र अहमद)

नजीबाबाद। होली हवन कल्याण समिति चौक बाजार नजीबाबाद की आवश्यक बैठक में आगामी 2 मार्च को होली जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाले जाने की रणनीति तैयार की गई। गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी नगर में होली जुलूस हर्षोल्लास के साथ निकालने के लिए मौहल्ला दरबाराशाह निवासी दीपक शर्मा दीपू के आवास पर हुई मीटिंग में हवन बोगी, ढोल, चंदौसी के तासे, डीजे, गुलाल बोगी समेत कई कार्यक्रम शामिल करने का निर्णय लिया गया। समिति के सदस्य अरूण शर्मा, संदीप वर्मा ने बताया कि आगामी 2 मार्च को सुबह 10 बजे नगर के रेलवे स्टेशन से होली जुलूस निकाला जाएगा। मीटिंग में विजय शर्मा टीटू, मनोज अग्रवाल, दीपक वालिया, दिनेश खन्ना, वंश शर्मा, मयंक शर्मा, सूरज वर्मा आदि मौजूद रहे।

प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को सीएम योगी ने दिया होली का उपहार

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर शनिवार को लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य जारी है। होली व दीपावली पर लाभार्थियों परिवारों को एक-एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। सीएम योगी ने इस अवसर पर दस लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सब्सिडी राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे।

सबका साथ-सबका विकास ही मंत्र-सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाओं और युवाओं से जोड़ने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि देश में केवल चार जातियां हैं। ये जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा हैं। इसमें सभी पंथ, संप्रदाय, मत और मजहब समाहित हैं। ऐसे में जब भी किसी योजना का लाभ दिया जाएगा तो उसका मंत्र केवल "सबका साथ, सबका विकास" ही होगा। कोरोना महामारी समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। यह सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है।

राष्ट्र सेवा और नशा मुक्ति का लिया संकल्प

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। तहसील क्षेत्र के ग्राम शेखुपुर झकडी में सुरेंद्रदास के आवास पर राष्ट्र सेवी संगठन के तत्वावधान में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और भारी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति के मूल मूल्यों को पुनर्जीवित करना रहा।

होली के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए-कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में होली के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला,नशा मुक्ति का सामूहिक संकल्प समारोह का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव नशा मुक्ति अभियान रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपस्थित युवाओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों की पवित्रता नशे के कारण भंग हो रही है। उन्होंने समाज से अपील की कि वे नशे जैसी कुरीतियों को त्यागकर स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें,कार्यक्रम के अंत में फूलों की होली खेली गई और सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामजीमल और संचालन उमेश सैन ने किया। इसके अलावा मुकेश शर्मा, होमपाल सिंह, करन सिंह , रोहताश सिंह, राकेश, चंद्रपाल, कैलाश, डालचंद, हरपाल सिंह, संजय आदि मौजूद रहे।

महिला दिवस से पहले 42 जनपदों के सरकारी विद्यालयों में शौचालय होंगे पूरी तरह क्रियाशील

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आठ मार्च की समय-सीमा तय
- बालिकाओं की गरिमा और सुरक्षा पर योगी सरकार का विशेष जोर
- 'प्रेरणा पोर्टल' पर फोटो अपलोड करना होगा अनिवार्य

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, अयोध्या, रामपुर समेत प्रदेश के 42 जनपदों के सभी सरकारी विद्यालयों में बने शौचालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि आठ मार्च तक सभी विद्यालयों के शौचालय उपयोग योग्य स्थिति में होने चाहिए। उन्होंने दोहराया कि केवल निर्माण कार्य पूरा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शौचालयों में स्वच्छता, नियमित सफाई, जल की उपलब्धता, बिजली व्यवस्था (जहां आवश्यक हो) और सुरक्षित दरवाजों की स्थिति भी सुनिश्चित की जाए।

बालिकाओं की उपस्थिति और ड्रॉपआउट पर सकारात्मक प्रभाव-सरकार का विशेष फोकस छात्राओं के लिए पृथक एवं सुरक्षित शौचालयों की उपलब्धता पर है। अधिकारियों का मानना है कि स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय सुविधा मिलने से छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ेगी, मासिक धर्म के दौरान सहजता होगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। महिला दिवस के अवसर पर यह पहल बेटियों को सम्मानजनक शैक्षिक वातावरण देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जा रही है।

'प्रेरणा पोर्टल' से होगी पारदर्शी निगरानी-शौचालयों की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए प्रेरणा पोर्टल पर फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक विद्यालय को शौचालय के अंदर और बाहर की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। इससे शासन स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में मरम्मत या जल कनेक्शन की आवश्यकता है, वहां तत्काल कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है।

समयबद्ध लक्ष्य, तय होगी जवाबदेही-सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आठ मार्च की समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय की जाएगी। आवश्यक बजट और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह अभियान न केवल बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि महिला सशक्तीकरण और सम्मान की भावना को जमीनी स्तर पर साकार करने का प्रयास है।

उन्नाव के मियागंज थाने में, अपर पुलिस अधीक्षक ने की, जनसुनवाई

थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायतें सुनी,त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

लोक तंत्र की शान

उन्नाव : उन्नाव के थाना मियागंज में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद ने 28 फरवरी दिन शनिवार को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की! इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से आए फरियादियों की ,शिकायतें सुनी! अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद ने प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया, उन्होंने सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक ध्यान से सुना और उन पर त्वरित निस्तारण करने पर जोर दिया! जनसुनवाई के बाद, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र ने, थानाध्यक्ष सफीपुर और संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि,सभी शिकायतों की निष्पक्ष समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए!

अंबेडकर पार्क के चारों ओर ठेले वालों ने फिर किया कब्जा, गंदगी के लग रहे अंबार

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः नगर की सुंदरता में चार चांद लग रहा अंबेडकर पार्क प्रशासन की अनदेखी के चलते फिर से ठेले खोमचे वालों की गिरफ्तार में आ गया है, बताते चले कि जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम, चल रहा है होली भी निकट करीब है और रमजान चल रहे है ईद भी करीब है और हमारे नगर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले अंबेडकर चौक को फिर कुछ सफाई के दुश्मनों ने गंदगी फैलाने के लिए अपने ठेलो के जाल से घेर लिया है, लगता है की हसनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर की गई कार्रवाई का असर अब खत्म हो गया है, जिसके चलते ठेले, खोमचे, फल व अन्य खाद्य सामग्री बेचने वालों के हौसले बुलंद हुए हैं और उन्होंने अंबेडकर पार्क को घेर लिया है और उनके द्वारा गंदगी परोसी जा रही है, इससे पूर्व जब पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई थी इन अतिक्रमण अतिक्रमकारीयो को हटाने की तो अंबेडकर पार्क की सुंदरता में और भी निखार गया था लेकिन पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते फिर से इस अतिक्रमण से अंबेडकर पार्क की सुंदरता ढक गई है, वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख वेद प्रकाश यादव ने पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं नगर पालिका अधिकारियों से इन अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग की है।

चिरंजीलाल कॉलेज ऑफ़ एजूकेशन डगरोली में सात दिवसीय शिविर का हुआ समापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : शुक्रवार को चिरंजी लाल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विशेष शिविर का समापन ग्राम बौनावाली डगरोली में हुआ, बताते चलें कि महाविद्यालय के स्वयंसेवी आसपास के क्षेत्र में घूम-घूम कर लोगों को स्वच्छता, स्वस्थ, शिक्षा, सड़क सुरक्षा ,महिला सशक्तिकरण , कौशल विकास हेतु युवा आदि अन्य विषयों को लेकर जागरुक कर रहे थे, जिसका शुक्रवार को सफल समापन हुआ। इस अवसर पर संस्थान निदेशक पुनीत अग्रवाल ने सभी को सफल शिविर के लिए बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहां की शिविर के मुख्य उद्देश्य कौशल विकास हेतु युवा पर केंद्रित होकर भविष्य में कार्य करने चाहिए। वहीं उन्होंने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण एवं जल शिक्षण विषय पर विशेष महत्व दिए जाने तथा अपनी प्रकृति को बचाने और प्राकृतिक जल संरक्षण स्रोतों को बचाने वह उन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ राकेश आर्य, विनोद गुप्ता, मनोज कुमार शर्मा, लोकेश कुमार, अतुल शर्मा , अजीत कुमार, अंजनी, अशोक, दीपक, नेहा सागर, प्रियंका, सृष्टि, शीतल, रितिक कुमार, मीनू, सोनिया, कोशिंदर , हिमांशी सहितसभी स्वयंसेवी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मुजफ्फरपुर में 3 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, 11 केवी कांटी फीडर में मेंटेनेंस कार्य को लेकर शटडाउन

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आज (28 फरवरी 2026) तीन घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। 11 केवी कांटी फीडर में मेंटेनेंस वर्क को लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटेगी। शटडाउन का असर डुमरी और आसपास के मोहल्लों पर पड़ेगा। कांटी फीडर से जुड़े अन्य छोटे इलाकों में भी इस दौरान आंशिक रूप से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तारों की मरम्मत, इंसुलेटर की जांच और फीडर की सफाई का काम बेहद आवश्यक है। इस तीन घंटे के अंतराल में जर्जर तारों को दुरुस्त किया जाएगा। जिससे बड़े फॉल्ट या ट्रिपिंग की समस्या से बचा जा सके। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि सुबह 10 बजे से पहले ही पानी की टंकियां भर लें। साथ ही, बिजली से चलने वाले उपकरणों और गैजेट्स (जैसे मोबाइल, लैपटॉप) को पहले ही चार्ज कर लें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अपने बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। मेंटेनेंस कार्य पूरा होते ही बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अगर इसके बाद भी किसी क्षेत्र में आपूर्ति शुरू नहीं होती है, तो उपभोक्ता नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या स्थानीय लाइनमैन से संपर्क कर सकते हैं।

घर में लगी आग, महिला की मौत, हादसे में पति भी घायल, चल नहीं पाती थी महिला, बेटा-बहू बाजार गए थे

पटना। पटना के करबिगहिया मुहल्ले में देर शाम एक मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 65 वर्षीय मालती देवी की झुलसने से मौत हो गई। उनके 75 वर्षीय पति बलीराम चौधरी घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मालती देवी पैरालिसिस से पीड़ित थीं और चलने-फिरने में असमर्थ थीं। आग लगने के दौरान वह खुद को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जा सकीं, जिसके कारण वह आग की चपेट में आ गईं। उनके पति बलीराम चौधरी को भी आग बुझाने के प्रयास में चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय घर का छोटा बेटा रवि शंकर चौधरी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाजार गया हुआ था। इसी दौरान अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। पड़ोसियों ने तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मालती देवी के पति बलिराम चौधरी ने बताया कि आग मेरे सामने लगी, जिसके बाद मैंने शोर किया। आसपास के लोगों ने मिलकर बुझाई। बलिराम चौधरी भी पैरालाइसिस के शिकार हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बलिराम चौधरी को बचा लिया। वृद्ध महिला आग में झुलस गई।

मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुरू की निशुल्क बस सेवा, सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती

मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने आम जनता के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरूआत की है। रेलवे स्टेशन और बैरिया बस स्टैंड से बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो होली के अवसर पर दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि देर रात ट्रेन से उतरने के बाद यात्री स्टेशन पर ही समय बिताते हैं या असुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। ऐसे में वे नशाखुरानी गिरोह या अन्य अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। पुलिस की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को न केवल आर्थिक राहत देना है, बल्कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ उनके घर तक पहुंचाना भी है। पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई इन बसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बस में एक ट्रेंड ड्राइवर के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। टीम यह सुनिश्चित करेगी कि रास्ते में यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षित अपने गांव तक पहुंच सके। निशुल्क बस सेवा शहर के रेलवे स्टेशन और बैरिया बस स्टैंड से शुरू होकर जिले के अलग-अलग ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक जाएगी। इसके तहत कांटी, मोतीपुर, बरूराज, साहेबगंज, पारू, सरैया, मड़वन, बोचहां, गायघाट, बेनीबाद, सकरा, मुरौल, तुर्की और कुढ़नी जैसे क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इन रूटों पर बसें देर रात तक परिचालन करेंगी, ताकि स्टेशन पर फंसे यात्रियों को मदद मिल सके। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान वाहन या संदिग्ध व्यक्ति के झांसे में आने के बजाय सुरक्षित और निशुल्क सेवा का लाभ उठाएं। पुलिस आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ का फायदा उठाकर नशाखुरानी गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस की यह बस सेवा ऐसे अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस मानवीय चेहरे की जमकर सराहना की है। कुल मिलाकर, बिहार पुलिस सप्ताह के तहत शुरू की गई यह सेवा न केवल खाकी के प्रति विश्वास बढ़ाएगी, बल्कि त्योहार की खुशियों को सुरक्षित बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगी।

12 लाख के चोरी के कपड़े बरामद, बदमाश गिरफ्तार मुजफ्फरपुर में 6 दिन पहले हुई थी वारदात

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की अहियापुर थाना पुलिस ने 12 लाख रुपये के कपड़ा चोरी कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी हुए कपड़ों के सभी 33 बंडल बरामद कर लिए हैं और इस मामले में पूर्वी चंपारण से एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर स्थित 'आर.के. इंटरप्राइजेज' के गोदाम में 21 फरवरी 2026 को हुई थी। चोरों ने देर रात दो पिकअप वैन के साथ आकर गोदाम का ताला काटा। वे अंदर घुसे और कपड़े के बंडलों को वैन में लादकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के बयान पर अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ टाउन टू, बिनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने मानवीय सूचनाओं और तकनीकी साक्ष्यों, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन शामिल हैं, के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी का माल पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गोदाम में छिपाया गया है। सूचना के आधार पर विशेष टीम ने हरसिद्धि में छापेमारी की और चोरी किए गए सभी 33 बंडल बरामद कर लिए। पुलिस ने मौके से कपड़ा दुकानदार मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी चोरी के माल को ठिकाने लगाने की तैयारी में था। एसपी ने आगे बताया कि हालांकि पुलिस ने माल बरामद कर लिया है और एक आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन इस पूरी घटना का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की टीमें फरार मास्टरमाइंड और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

'नीट रेप-मौत केस में पॉक्सो क्यों नहीं लगाया'

कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, एसआईटी-एजेंसी से पूछा- आपको मनीष रंजन की जरूरत है या नहीं

एजेंसी, पटना

पटना में NEET छात्रा मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई ढाई घंटे तक चली। मनीष रंजन को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब याचिका पर 2 मार्च को सुनवाई होनी है। CBI को आज भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। CBI से पूछा है कि आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया? 17 जनवरी तक केस की जांच चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार रौशनी कर रही थी, फिर SIT ने जांच की। इसके बाद 12 फरवरी को CBI ने 307 का केस दर्ज किया। CBI को जांच करते हुए 15 दिन हुए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन को लेकर अब तक आपने क्या जांच की? क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है? आपने अपने केस में तो पॉक्सो एक्ट लगाया नहीं है।

आपके पास तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। इस पर आप जवाब दीजिए कि मनीष रंजन की जरूरत आपको है या नहीं? SIT से भी यही सवाल कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने कहा कि मनीष

पर आरोप क्या है? इसके खिलाफ सबूत क्या है? SIT ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये प्रभाशाली व्यक्ति हैं। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि, अब जांच CBI कर रही है। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार भी मौजूद था।

रौशनी और एसआईटी के बयान अलग-अलग थे: कोर्ट ने केस चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार और शुरुआत में IO रही रौशनी कुमारी से कई सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि आपने कितनी तारीख तक केस की जांच की? मनीष रंजन पर क्या आरोप है? इसके खिलाफ क्या सबूत मिले? आपने अपनी जांच में क्या-क्या जब्त किया? सबूतों को 24 घंटे में कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? रौशनी ने छात्रा का मोबाइल और हॉस्टल का DVR जब्त किया था। कोर्ट ने पूछा कि इसे आपने अपने पास क्यों रखा? FSL जांच क्यों नहीं कराई? कोर्ट से इसकी अनुमति क्यों नहीं ली? अपना पक्ष रखते हुए रौशनी ने कहा कि मैंने सभी चीज SIT को 17 जनवरी को सौंप दिया था। मौके पर ही SIT ने कहा कि नहीं, हमें 24 जनवरी को मिला था। दोनों के बयान मेल नहीं खाए। पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। SIT को लीड कर सचिवालय SDPO-1 डॉ. अन्नू कुमारी से भी सवाल किया गया है। मनीष रंजन कब-कहां थे? वो बिहार से बाहर कब गए? उन्हें कब पकड़ा? उनका स्टेटमेंट क्या था? सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट को डॉ. अन्नू ने बताया कि CDR खंगाला गया है। उससे इनके लोकेशन को मिलाया गया है।

बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा पोर्टिको में नोट उड़ाया

एजेंसी, पटना

विधानसभा का बजट सत्र का कल आखिरी दिन था। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद जब जदयू के कुचायकोट के विधायक पप्पू पाण्डेय बाहर निकले। इस दौरान पप्पू पांडे होली के बक्शीश के रूप में वहां मौजूद कर्मचारियों को पैसे बांटने लगे। यद देख कर्मचारियों के भीड़ जुट गई। इसके बाद पप्पू पाण्डेय ने 500 के नोट हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। विधानसभा पोर्टिको में मौजूद तमाम कर्मचारी यहां तक की मार्शल भी पैसे लूटने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं कार्रवाई: विधानसभा कैंपस के अंदर पैसे बांटना अनुशासनहीनता मानी जाती है। जिस तरह से पोर्टिको से पैसे उड़ाए गए वो विधायक के लिए संसदीय परंपरा के खिलाफ मानी जाती है। इस मामले में कार्रवाई करने का पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष मामले को संज्ञान में लेकर इसकी पूरी जांच कर सकते हैं। साथ ही मार्शल को बुलाकर पूछताछ भी किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष अपना अधिकार का पालन करते हुए विधायक को हिदायत भी दे सकते हैं। साथ ही मार्शल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

छठी बार जीत हासिल कर बने विधायक: गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधायक का नाम अमरेंद्र कुमार पाण्डेय है, जो पप्पू पाण्डेय के नाम से भी जाने जाते हैं। वे छठी बार जीत हासिल कर विधायक बने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने 24365 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी हरिनारायण सिंह को मात दी थी। अमरेंद्र कुमार पाण्डेय बिहार विधानसभा में प्रश्न एवं ध्यान आकर्षित करने वाली समिति के सह अध्यक्ष भी हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के राज्य महासचिव भी हैं। 2020 के आम चुनाव में उन्होंने पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे को भी हराया था ।

पीयू चुनाव में 37.84% वोटिंग साइंस कॉलेज में फायरिंग

एजेंसी, पटना

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। कुल 37.84% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान पटना साइंस कॉलेज में गोली चली है। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। फायरिंग किसने की इसे लेकर जांच चल रही है। इससे पहले पटना कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए खड़े तेजप्रताप के कैंडिडेट रिंकल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने पीरबहोर थाने के बाहर हंगामा किया। पुलिस रिंकल को VC ऑफिस लेकर जा रही थी। इस दौरान छात्र नारेबाजी करने लगे। PU मुर्दाबाद और वॉइस चांसलर मुर्दाबाद के नारे लगे। छात्र इस दौरान VC ऑफिस के गेट के सामने लेट गए।

पुलिस रिंकल यादव को टांगकर थाने लाई। इस दौरान रिंकल को उठाकर गाड़ी में बैठाया गया। उन्होंने पैर गाड़ी से बाहर निकाल लिए, पुलिस ने पैर अंदर किए और थाने लाई। स्टूडेंट्स और पुलिस में झूमाझटकी

◆ बैलेट पेपर में गलत नाम होने पर तेजप्रताप के कैंडिडेट का हंगामा टांगकर ले गई पुलिस

भी हुई। कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का आरोप है- नॉमिनेशन के वक्त पेपर पर रिंकल यादव का नाम था, लेकिन चुनाव के दौरान बैलेट पेपर में रिंकल कुमार है। वो छात्र नेता है, पिछले 5 साल से इस यूनिवर्सिटी में संघर्ष कर रहा है।

नर्स पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पति ने खुद डायल 112 पर दी सूचना

एजेंसी, पटना

दानापुर थाना क्षेत्र के पूर्वी गोला रोड में शुक्रवार रात एक पति ने अपनी नर्स पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना होली पर ससुराल न जाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनू ने अपने दो साल के बेटे को पहले छपरा स्थित अपने घर पहुंचाया। फिर देर रात दानापुर लौटकर डायल 112 पर फोन कर पुलिस को हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को उसके घर से हिरासत में ले लिया है। मृतका की पहचान पीएमसीएच में हेड नर्स के रूप में कार्यरत चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। आरोपी पति का नाम सोनू कुमार सिंह है।

होली पर ससुराल छपरा जाने को लेकर हुआ विवाद: हिरासत में लिए गए आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि, 'शुक्रवार शाम को उसने अपनी पत्नी चांदनी से होली पर ससुराल छपरा जाने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सोनू ने चांदनी को जोर से चांटा मारा, जिससे उसके कान से खून निकलने लगा। इसके बाद उसने चांदनी का गला

दबाया और सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी।'

ऑनलाइन गेम में चार लाख रुपये हारा था पति: मृतका चांदनी की बहन ब्यूटी कुमारी ने बताया कि, 6 फरवरी 2023 को चांदनी की शादी सोनू के साथ हुई थी। उनका दो साल का बेटा भी है। ब्यूटी ने आरोप लगाया कि सोनू ऑनलाइन गेम में चार लाख रुपये हार गया था, जो चांदनी ने दिए थे। चांदनी ने एक जमीन भी खरीदी थी और शुक्रवार दोपहर को ही सोनू को वह जमीन दिखाई थी। ब्यूटी कुमारी ने यह भी बताया कि ससुराल वाले अक्सर रुपयों के लिए चांदनी को परेशान करते और मारपीट करते थे। शुक्रवार को भी सोनू

दानापुर से गिरफ्तार, पूछताछ जारी

ने चांदनी की बुरी तरह पिटाई की थी और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं।

रात 2 बजे फोन कर परिजनों को खुद दी जानकारी: मृतका के बहनोई कृष्णा सिंह ने बताया कि, शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे उनके साले सोनू ने फोन कर बताया कि मेरी बड़ी साली चांदनी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। जब घर के अंदर गया तो देखा कि चांदनी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था और हत्यारा पति सोनू सिंह वहां बैठा हुआ है। उसे पुलिस हिरासत में लेकर थाना ले आई।

पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा, जांच जारी: थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि, 'मामले की जांच जारी है। मृतका के परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर आगे की करवाई की जायेगी।' पुलिस ने कमरे से चांदनी का शव कब्जे में लिया। शनिवार सुबह अनुमंडलीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।

गांधी सेतु पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला, मुजफ्फरपुर से पटना आ रहे इंजीनियर का हाथ कटा

एजेंसी, पटना

पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु पर गायघाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार इंजीनियर को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार का एक हाथ कटकर पुल के नीचे गिर गया। घायल की पहचान इंजीनियर मोहम्मद अकिल के तौर पर हुई है, जो पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वह मुजफ्फरपुर में यूपीएस बनाने का काम करते हैं। वे रोजाना की तरह काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे, तभी इस हादसे के शिकार हो गए।

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक हाजीपुर से पटना लेन पर तेज रफ्तार से आ रहा था। पिलर संख्या 46 के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बाइक से घर

लौट रहे मोहम्मद अकिल को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया।

घायल की स्थिति नाजुक, PMCH रेफर: हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल अकिल को तुरंत नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद भी ज्यादा खून बहने से हालत बिगड़ने लगा। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

फरार ट्रक ड्राइवर की पहचान की कोशिश जारी: घटना की सूचना मिलते ही आलमगंज थाना पुलिस और ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरार ट्रक और उसके ड्राइवर की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आलमगंज थाना प्रभारी राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि, घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है।' बताया जा रहा है कि गांधी सेतु के जर्जर हिस्से में चल रहे निर्माण कार्य के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संकरी लेन और अव्यवस्थित ट्रैफिक के चलते इस पुल पर अक्सर हादसे होती रहती है।

पटना के आईजीआईसी में 10 बच्चों का सफल हार्ट ऑपरेशन

एजेंसी, पटना

पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (IGIC) में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत बिहार के 10 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है। 26 और 27 फरवरी को हुए इन ऑपरेशनों में अत्याधुनिक डिवाइस क्लोजर तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे बच्चों को नया जीवन मिला। ये सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत पूरी तरह निःशुल्क किए गए। अत्याधुनिक डिवाइस क्लोजर तकनीक के जरिए ऑपरेशनों में छाती खोलने या बड़ा चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैथ लैब के माध्यम से नसों के जरिए हृदय तक पहुंचकर एक विशेष डिवाइस लगाया गया, जिसने हृदय में मौजूद छेद को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। इस तकनीक से दर्द कम होता है, संक्रमण का खतरा घटता है और मरीज की रिकवरी तेजी से होती है।

ऑपरेशन टीम में नई दिल्ली के विशेषज्ञ भी रहे शामिल: संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की गई। ऑपरेशन टीम

में नई दिल्ली के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज अवस्थी और आईजीआईसी की डॉ. पूजा कुमारी शामिल थीं। विशेषज्ञों की इस टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से इन जटिल मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया। आरबीएसके के नोडल ऑफिसर डॉ. बीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत अब तक बिहार में 462 बच्चों का इसी आधुनिक तकनीक से सफल और निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

होली से पहले मुर्गियों में मिला खतरनाक बर्ड फ्लू

एजेंसी, पटना

पटना में बर्ड फ्लू खतरनाक रूप लेते जा रहा है। पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग के जू-सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौवों और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4575 मुर्गियों को मारा गया है। 9662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट किया गया है। जू-सेक्टर पार्क और संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। H5N1 बर्ड फ्लू को कोरोना से भी खतरनाक माना जाता है। इसका जानवरों से इंसानों में फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। इधर ऐसे मामले सामने आने के सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को हाईअलर्ट पर रखा है।

पटना में 6000 मुर्गियों को दफनाया गया: पटना के चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में 6000 मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गईं हैं। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने सभी मुर्गियों को दफना दिया है। संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके को सेनिटाइज किया गया। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मुर्गी फार्म क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह इलाका एयरपोर्ट के पास चितकोहरा पुल के नीचे स्थित है। क्षेत्र में बड़ी आबादी रहने के कारण प्रशासन सतर्क है।

बैंकॉक से दो गुना मुंबई-पटना फ्लाइट का किराया

एजेंसी, पटना

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से होली मनाने के लिए घर आना बिहार के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ट्रेनों के सीट फुल हैं। रेलवे ने 200 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाईं, लेकिन इनमें भी सीट नहीं मिल रहे। कंफर्म टिकट के लिए अब सिर्फ तत्काल कोटे से उम्मीद है। बड़े शहरों से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया भी बढ़ गया है। मुंबई-पटना फ्लाइट का किराया शुक्रवार दोपहर तक 1 मार्च के लिए 23,453 रुपए है। यह इसी तारीख को दिल्ली से बैंकॉक के किराया (9,483 रुपए) से दो गुना से ज्यादा है। इधर, होली में बिहार आने वालों के लिए दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से परिवहन निगम की ओर से 51 स्पेशल बसों को चलाया रहा है। इन बसों में 90% सीटें फुल हो गई हैं। यात्रियों को ऑन स्पॉट टिकट मिल रहा है। होली के बाद लौटने वालों के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गयाजी सहित अन्य जिलों से देश के विभिन्न शहरों के लिए 118 बसों का परिचालन

होगा। वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। होली के मौके पर बिहार आने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से पटना के लिए सीधी फ्लाइट का किराया कितना है? बसों की क्या हालत है?

लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़, जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं: दुरंतो और राजधानी जैसी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर के चलते किराया डेढ़ गुना बढ़कर 3515 तक पहुंच गया है, लेकिन इनमें भी सीट खाली नहीं। लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ है। कंफर्म

❐ रेलवे की 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में नो रूम, फ्लेक्सी फेयर भी डेढ़ गुना हुआ

टिकट नहीं मिलने पर भी लोग ट्रेनों में सवार हो जा रहे हैं। जनरल बोगी में तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। भीड़ बढ़ने के चलते रेलवे ने 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये हैं..

ट्रेनों में 30 फीसदी यात्री बढ़े: होली को लेकर शुक्रवार को पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या 30 फीसदी तक बढ़ गई, लेकिन, भीड़ नियंत्रण करने के लिए न तो RPF एक्टिव है और न GRP। टीम शुक्रवार शाम 5:50 बजे जंक्शन पर पहुंची तो 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर पटना-गया पैसेंजर आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की खचाखच भीड़ थी। ट्रेन के आने की घोषणा होते ही करीब 25 फीसदी यात्री प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर उतर गए। देखते ही देखते ट्रैक यात्रियों से भर गया। ट्रैक प्लेटफॉर्म जैसा बन गया।

संक्षिप्त समाचार

चौरसिया मैरिज गार्डन छपरा में शादी के समय रोड जाम एंबुलेंस बीच में फांसी

लोकतंत्र की शान हसन रस्सी जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेशः कटनीः छपरवाह मेन रोड पर अवैध बारात घर चौरसिया मैरिज गार्डन से आए दिन घंटों घंटों का जाम लगा रहता है ग्रामीण जन परेशान रहते है कई दर्जनों ग्रामों के जाने का यह एक मात्र रास्ता है कल एक एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही कोई देखने वाला नहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं बारात घर संचालक को व्यवस्था राहगीरों के लिए करनी चाहिए जिम्मेदारों तक यह बात पहुंचाये इस तरह की घटनाएं शादी के समय आम बात हो गई जिला प्रशासन को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए ऐसे गार्डन जो शादी के लिए रोड पर बना रखे हैं उन्हें समझाइए देकर उन पर कार्रवाई करें

यमुनानगरःबच्चों की सुरक्षा संग मनाएं होली, मिशन वात्सल्य की अपील

लोकतंत्र की शान : यमुनानगर। रंगों के पर्व होली को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाने को लेकर मिशन वात्सल्य के तहत जिला प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि उत्सव की खुशियों के बीच बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यमुनानगर में कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने शनिवार को नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सकारात्मक मूल्यों का प्रतीक है। ऐसे अवसरों पर बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्सव के दौरान रासायनिक रंगों के उपयोग से बच्चों की त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही पानी के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की कि छोटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, ताकि वे किसी दुर्घटना या अनुचित गतिविधि का शिकार न हों। सार्वजनिक स्थानों पर जबरन रंग लगाने, छेड़छाड़ या असामाजिक व्यवहार से दूर रहने का भी आग्रह किया गया है, जिससे त्योहार की गरिमा बनी रहे। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण तंत्र को सक्रिय रखते हुए लोगों से कहा गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ हिंसा, शोषण या उपेक्षा जैसी स्थिति की जानकारी मिले तो तुरंत बाल सहायता हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

फरीदाबाद : एक्सपायरी सामान बेच रहे किरयाना स्टोर पर छापेमारी, सेंपल लिए

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। एनआईटी क्षेत्र की डबुआ कालोनी में एक्सपायरी सामान बेच रहे एक किरयाना स्टोर पर शनिवार को सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान जब्त किया। इसके अलावा सेंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। टीम को राजेश किरयाना स्टोर पर एक्सपायरी डेट के दूध, दही, पनीर और अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थों को सस्ते दामों पर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकान में रखे खाद्य उत्पादों की जांच की। जांच में पाया गया कि करीब 70 लीटर टोंड दूध, 15 लीटर फुल क्रीम दही, 4 किलो पनीर, 5 पैकेट घी, 25 छोटी कैम्पा की बोतलें सहित कई अन्य पैकेट बंद खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। आरोप है कि दुकान संचालक इन उत्पादों को कम कीमत का लालच देकर ग्राहकों को बेच रहा था, जिससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। टीम ने मौके पर ही सभी संदिग्ध और एक्सपायरी खाद्य सामग्री को जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से फूड प्वाइजनिंग, उल्टी-दस्त, पेट दर्द, संक्रमण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से दूध और दुग्ध उत्पादों के खराब होने पर उनमें बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो सकते हैं। कार्रवाई के दौरान विभाग ने कुछ खाद्य उत्पादों के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

251 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप के साथ तस्कर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में अवैध नशा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान अभियान प्रहार 2.0 के अंतर्गत सीधी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सेमरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के एक बड़े तस्कर को भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र हेमंत चौहान के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव व एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के नेतृत्व में थाना सेमरिया पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बढ़ौरा बनिया डोल निवासी जगदीश उर्फ बेबी भुजवा अवैध नशीली कफ सिरप का भंडारण कर रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में कबूला कि उसने नशीली दवाओं की खेप अपने खेत की मेड़ में गुलमेहदा की घनी झाड़ियों और जमीन के अंदर छिपा रखी है। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान पर तलाशी ली, जहां 15-15 लीटर के दो ढक्कन बंद डिब्बों और झाड़ियों में छिपाकर रखी गई कुल 251 शीशी आनरेक्स नशीली कफ सिरप बरामद की गई। जिसकी कीमत कीमत 1,25,500 रुपए आंकी गई है एवं 1 हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, 1 कीपैड मोबाइल भी बरामद की गई। कुल जप्त संपत्ति की कीमत लगभग 1,56,000 रुपए आंकी गई। कार्रवाई में आरोपी जगदीश भुजवा उर्फ बेबी 45 वर्ष के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21, 22, 29 एवं ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम की धारा 5/13 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे जेल भेजा गया है। नेटवर्क के अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक केदार परौहा थाना प्रभारी सेमरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक विकाश सिंह चौकी प्रभारी बम्हनी, सउनि भूपेन्द्र बागरी, प्रआर पंकज विश्वकर्मा, आरक्षक मनीष शुक्ला, अमित तिवारी, विनीत सिंह, प्रकाश सिंह, रवी सिंह एवं सतीश तिवारी चौकी बम्हनी का विशेष योगदान रहा।

सीधी विधायक ने विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उठाया मुद्दा

लोकतंत्र की शान

सीधी। विधायक श्रीमती रीती पाठक ने मध्यप्रदेश विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े सीधी नगर के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पुराने बस स्टैंड परिसर में प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तथा सीवर लाइन परियोजना की स्वीकृति जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा। विधानसभा में उठाए गए प्रश्न में श्रीमती रीती पाठक ने बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा पुराने बस स्टैंड को हटाकर नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु अब तक न तो निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हुई और न ही निर्माण कार्य शुरू हो सका। उन्होंने कार्य में देरी के कारणों एवं निर्माण प्रारंभ होने की समय-सीमा स्पष्ट करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सीधी नगर पालिका क्षेत्र में बिना रेरा पंजीयन के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी सदन में उठाया। पिछले तीन वर्षों में चिन्हांकित अवैध कॉलोनियों की संख्या एवं उन पर की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी, ताकि आम नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। श्रीमती रीती पाठक ने सीधी नगर के लिए लंबे समय से लंबित सीवर लाइन निर्माण परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर भी प्रश्न किया और कहा कि बढ़ती आबादी के मद्देनजर व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विधानसभा में इन जनहित के विषयों को उठाकर श्रीमती रीती पाठक ने सीधी नगर के अधोसंरचनात्मक विकास और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अपनी सक्रियता दर्शाई है।

दिव्यांग छात्र से मार पीट करने के प्रकरण में प्रधानाध्यापक निलंबित

लोकतंत्र की शान

सीधी। कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा जारी हुआ आदेश, बाल कल्याण समिति की जांच में आरोपों की पुष्टि रीवा संभाग के कमिश्नर द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय मधुरी, जिला सीधी के प्रधानाध्यापक रामसहाय साकेत को दिव्यांग छात्र से कथित दुर्व्यवहार एवं कदाचार के गंभीर प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास, मधुरी में अध्ययनरत कक्षा 8 के एक दिव्यांग छात्र के साथ मारपीट एवं अपमानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में यह उल्लेख किया गया था कि छात्र के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से अनुचित व्यवहार किया गया, जिससे छात्र भयभीत एवं मानसिक रूप से आहत हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रकरण की जांच जिला बाल कल्याण समिति, सीधी से कराई गई। बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए निरीक्षण, छात्र एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह पाया गया कि दिव्यांग छात्र के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। समिति ने इसे गंभीर प्रकृति का प्रकरण मानते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

4 माह के मासूम का अपहरण प्रयास नाकाम

मां की सतर्कता से बची जान, जंगल की ओर भागा संदिग्ध

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के थाना मड़वास क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कतरवार के दाड़ीटोला में शनिवार दिन के करीब 9 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। पहाड़ किनारे बने घर में सो रहे चार माह के मासूम बच्चे को एक अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले जा रहा था। तभी बच्चे की मां की नजर उस पर पड़ गई। जैसे ही मां ने शोर मचाया पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। जहां घिरता देख घबराया संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को जमीन पर फेंककर जंगल की ओर भाग निकला। जब परिजन और ग्रामीण बच्चे के पास पहुंचे तो वह बेहोश अवस्था में पड़ा मिला। यह दृश्य देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बच्चे के पिता प्रवेश कुशवाहा ग्राम कतरवार के निवासी हैं। उनका घर दाड़ीटोला के पहाड़ी किनारे स्थित है, जहां सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। जिले के थाना मड़वास पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के जंगल और संभावित रास्तों पर सर्चिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध की पहचान के प्रयास जारी हैं और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जहां फिलहाल चार माह का मासूम अस्पताल में बेहोश है और उसकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मां की नजर न पड़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

सेम्पल लेने तक सीमित खाद्य औषधि विभाग की कार्रवाई

- कार्रवाई का भय दिखाकर की जाती हैं वसूली
- अपमिश्रित खाद्य सामग्रियों के विक्री में आई तेजी

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री बेरोकटोक चल रही है। कार्रवाई के नाम पर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा महज दुकानों में अवैध वसूली की जाती है। आंकड़ों की खानापूर्ति के लिये कुछ दुकानों से मिलावटी खाद्य सामग्रियों के सेम्पल भी लिये जाते हैं लेकिन बाद में कितने पर कार्रवाई होती है इसकी जानकारी कभी सार्वजनिक नही की जाती। लिहाजा मिलावटखोरी में लगे व्यवसायी बेखौफ होकर ग्राहकों से भारी भरकम कीमत वसूलने के बाद भी उन्हें शुद्ध खाद्य सामग्री देने के बजाय मिलावटी पकड़ा रहे हैं। मिलावट शब्द अपने आप मे ही विनाशकारी है। मगर जब वह मिलावट खाद्य सामग्री मानव शरीर के अंदर पहुंच जाएगी तो उसके क्या परिणाम इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान में जिले भर में अत्यधिक मुनाफा कमाने की लालच में दुकानदार और बड़े ब्यापारी खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल खेलते है। जानकारों के अनुसार किराना दुकानों में आटा, दाल, चावल, सरसो तेल, वनस्पति घी, मसाला, नमकीन, खाद्य तेल सहित खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का धन्धा तेजी के साथ फल फूल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के नाम पर सिर्फ दुकानों से खाद्य पदार्थों के सेम्पल ले लेते है और फिर उन सैम्पलों की जांच का क्या होता है इसका किसी को भी पता नहीं होता है। मिलावट के आतंक से गरीब अमीर सभी आतंकित है। हर तरफ मिलावट ही मिलावट देखने को मिल रहा है। दूध में पानी और शुद्ध देसी घी में वनस्पति की मिलावट की बात सुनी जाती थी मगर अब सभी खाद्य वस्तुओं में मिलावट देखने और सुनने को मिल रहा है। मिलावट खोरी के चलते खाद्य सामग्री का सेवन करने से लोगो के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावट करने वाले दुकानदार कानून की पहुच से काफी दूर है। तहसील मुख्यालयों के आसपास व ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ो किराने की दुकाने बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही है जहां जीएसटी का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन के आदेशो को दर किनार करते हुए खाद्य सामग्री के विक्रेता ऊंचे दामो में बेचकर गरीब जनता की जेब काट कर दुकानदार मालामाल हो रहे है जबकि मिलावट करने को एक गम्भीर अपराध माना गया है।

दीनदयाल रसोई घर का निरीक्षण

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी : निगमायुक्त ने बस स्टैंड स्थित दीन दयाल रसोई घर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले नागरिकों की संख्या, निर्धारित शुल्क, बैठक व्यवस्था एवं संचालन प्रणाली की जानकारी ली।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वच्छता, पेयजल की शुद्धता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। रसोई परिसर में नियमित साफ-सफाई एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए।

बरगवां स्कूल के जर्जर भवन को हटाने के निर्देश–मदन मोहन चौबे वार्ड स्थित बरगवां स्कूल के निरीक्षण के दौरान शाला स्टाफ से चर्चा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जर्जर भवन को तत्काल हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पठन-पाठन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने हेतु शाला भवन की आवश्यक मरम्मत एवं संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के निर्देश सहायक यंत्री को दिए गए।

सांसद के सौजन्य से गंगा स्नान एवं अयोध्या धाम के लिए दल रवाना

लोकतंत्र की शान

सीधी। क्षेत्र के लोकप्रिय एवं कर्मठ सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के सौजन्य मार्गदर्शन एवं विशेष पहल पर लोकसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्षों एवं संगठन के पदाधिकारियों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्रातः 9 बजे सीधी से पवित्र गंगा स्नान एवं अयोध्या धाम में श्री रामलला जी के दर्शन-पूजन हेतु श्रद्धापूर्वक रवाना हुआ। प्रस्थान के समय वातावरण पूर्णतः भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण रहा। सभी पदाधिकारियों ने यात्रा के पूर्व विधिवत पूजन-अर्चन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति, उन्नति एवं समग्र विकास की कामना की। उपस्थित जनसमूह ने यात्रियों को शुभकामनाएँ देते हुए मंगलमय यात्रा की कामना की। यह आध्यात्मिक यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकता, समर्पण एवं राष्ट्रहित के प्रति दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित करती है। अयोध्या धाम में श्री रामलला जी के दर्शन के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल द्वारा देश एवं प्रदेश की उन्नति तथा जनकल्याण हेतु विशेष प्रार्थना भी की जाएगी। यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की गई हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर विशेष रूप से चुरहट क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही, जिनमें खड्डी मंडल अध्यक्ष यश सिंह , हनुमानगढ़ मंडल अध्यक्ष बुद्धिसेन साहू , पटपरा मंडल अध्यक्ष विनोद पटेल, चुरहट मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह 'ओपी', पडखुरी मंडल अध्यक्ष रजनीश शुक्ला , रामपुर मंडल अध्यक्ष विजय शंकर चोड़गड़ी मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों में इस धार्मिक यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया तथा इसे आध्यात्मिक ऊर्जा एवं सांस्कृतिक जागरूकता का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

कृषि उपज मंडी कटनी का बर्खास्त लिपिक अवैध वसूली के व्यापारियों ने लगाए आरोप, कलेक्टर को दिया शिकायती पत्र

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। कृषि उपज मंडी कटनी के फल एवं सब्जी व्यापारियों ने मंडी के बर्खास्त लिपिक पर अवैध वसूली के लिए परेशान करने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायती पत्र दिया है। व्यापारियों ने कहा की बर्खास्त लिपिक के द्वारा मंडी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर व्यापारियों के खिलाफ अनावश्यक कार्यवाही के दबाव बनाते हुए पत्र जारी कराए जाते हैं।<शिकायती पत्र के माध्यम से फल एवं सब्जी व्यापारी संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि चन्द्रशेखर अग्निहोत्री पिता भगवान दास अग्निहोत्री बर्खास्त लिपिक कृषि उपज मंडी कटनी के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कटनी के अधिकारियों पर दबाब बनाकर बार बार अनावश्यक पत्र जारी करवाकर अवैध वसूली करने के आशय से हम सभी फल सब्जी व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चन्द्रशेखर अग्निहोत्री का प्रत्यक्ष रूप से मंडी के शासकीय कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप रहता हैं जिसका प्रमाणीकरण आज दिनांक से पिछले 15 दिवसों के समय सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मंडी प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई रिकार्डिंग फुटेज से भी किया जा सकता हैं। उक्त लिपिक को वर्ष 2012 में लखमीचंद्र मटानी से दस हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चन्द्रशेखर अग्निहोत्री अपनी हरकतों से बाज नही आ रहा। प्रतिदिन मंडी के शासकीय कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर मंडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की झूठी शिकायते कर व उन पर दबाब बनाकर उनसे अनुचित कार्य करवाता रहता हैं। व्यापारियों ने शिकायती पत्र के जरिए उक्त लिपि के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

ईरान-इजराइल जंग के चलते एअर इंडिया की फ्लाइट मुंबई लौटी, दिल्ली से इजराइल जा रहा था विमान

नई दिल्ली/मुंबई। ईरान पर ईजराइन और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच इजराइल एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। इस वजह से एअर इंडिया ने शनिवार को अपनी दिल्ली-तेल अवीव फ्लाइट मुंबई डायवर्ट कर दी। 28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव के लिए ऑपरेट करने वाली AI139, इजराइल में एयरस्पेस बंद होने और यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के हित में भारत लौट रही है। फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया है। साथ ही एअर इंडिया और इंडिगो ने हमले के बाद मिडल ईस्ट अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को रोक दिया है। इसी के साथ एअर इंडिया ने इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए +91 1169329333, +91 1169329999 नंबर भी डारि किए हैं। दरअसल, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं और हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि हम अपने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सुरक्षा माहौल का आकलन करते रहेंगे और जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन को पहले से एडजस्ट करेंगे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट से ऑपरेट की गई यह फ्लाइट पांच घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रही और एयरलाइन ने सऊदी अरब के एयरस्पेस में आने पर वापस लौटने का फैसला किया। एयर इंडिया ने भी इस अचानक हुई स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया। इस बीच, इंडिगो ने कहा कि वह ईरान और उसके एयरस्पेस से जुड़े रीजनल अपडेट्स पर करीब से नजर रख रहा है।

राजस्थान-एमपी में तापमान 33° के पार

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फरवरी के महीने में अप्रैल जैसी धूप निकल रही है। दोनों राज्यों के कई शहरों में गुरुवार को तापमान 33°C के पार दर्ज हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 36.5°C दर्ज हुआ। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में तापमान 35.2°C रिकॉर्ड हुआ। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 31°C के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर भी मौसम बदल गया है। शुक्रवार शाम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित मनाली में ऊंचे इलाकों पर अचानक बर्फबारी हुई। रोहतांग स्थित अटल टनल पर बर्फबारी के कारण कुछ देर के लिए जाम की स्थिति रही। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पांच जिलों में अगले कुछ दिनों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पंजाब और चंडीगढ़ में धुंध और तेज हवा के बीच कुछ इलाकों में यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सड़क यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

नामीबिया, साउथ-अफ्रीका के बाद बोत्सवाना से आए 9 चीते

श्योपुर। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार सुबह 9 और चीते लाए गए। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीता वायुसेना के विशेष विमान से पहले ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाए गए। कूनो में अब चीतों का कुनबा 36 से बढ़कर 45 गया है। गांधी सागर अभयारण्य के तीन चीतों को मिलाकर देश में 48 चीते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह विशेष विमान से ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पहुंचे। सुबह करीब 9:20 बजे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से क्रेट का हैंडल घुमाकर दो चीतों को क्वारंटीन बाड़े में रिलीज किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई खेप में मादा चीतों की अधिक संख्या से कूनो में लिंगानुपात (Sex Ratio) बेहतर होगा, जिससे भविष्य में प्राकृतिक प्रजनन की संभावनाएं और प्रबल होंगी। जानकारों के मुताबिक, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना के चीतों के शामिल होने से कूनो में जेनेटिक विविधता (Genetic Diversity) और मजबूत होगी। कूनो में अब वयस्क चीतों की संख्या में 18 मादा और 16 नर शामिल हैं। सभी 9 चीतों को अगले एक महीने तक विशेष क्वारंटीन बाड़ों में विशेषज्ञों और डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा जाएगा। तीन अलग-अलग देशों के चीतों का एक साथ होना इस प्रोजेक्ट की लंबी अवधि की सफलता के लिए निर्णायक साबित होगा।

ओडिशा में महिला का रेप और मर्डर, पहले प्रेमी ने गलत काम किया और छोड़कर भागा

भुवनेश्वर। ओडिशा के महिला (23) की रेप के बाद हत्या कर दी गई। घटना जगतसिंहपुर जिले की है। महिला के साथ दो बार रेप किया गया। इसके बाद मर्डर हुआ। जगतसिंहपुर एसपी अंकित कुमार वर्मा के मुताबिक 22 फरवरी को युवती सुबह 10 बजे घर से लापता हुई थी। उसके प्रेमी सोमनाथ ओझा ने शादी करने की बात कहकर मंदिर में बुलाया था। सोमनाथ युवती को अपने साथ सुनसान जगह ले गया, वहां उसका रेप किया। बाद में युवती को राहामा बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया था। वहां युवती को शुभम कुमार नाम का युवक मिला। वह युवती को मदद करने के बहाने अपने रूम पर ले गया। वहां उसका रेप किया और इमारत की चौथी मंजिल से फेंककर युवती की हत्या कर दी।

पुलिस बोली- दोनों आरोपी गिरफ्तारः पुलिस ने बताया कि शुभम झारखंड के धनबाद का रहने वाला है। जब युवती बस स्टैंड पर अकेली थी। तब उसने युवती से बात की। उससे मदद का भरोसा दिया था। सुरक्षित जगह पहुंचाने का भरोसा दिलाया था। युवती का शव 23 फरवरी को मिला था। पुलिस ने बताया कि युवती के भाई ने पहले तिर्तोल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 23 फरवरी को बहन का शव मिलने के बाद उसने 25 फरवरी को पारादीप मॉडल थाने में दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है।

धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का नोटिस, रेजिडेंशियल प्लॉट पर पैथोलॉजी लैब चलाने का आरोप

रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। मामला रांची के हरमू इलाके में स्थित H-10A आवासीय प्लॉट से जुड़ा है। बोर्ड का आरोप है कि यह प्लॉट केवल आवासीय उद्देश्य से आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान में वहां कथित तौर पर एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। नोटिस में धोनी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्लॉट का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड ने हाल के दिनों में ऐसे कई मामलों की समीक्षा शुरू की है, जिनमें आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई चर्चित हस्ती। बोर्ड का उद्देश्य आवंटन की शर्तों को सख्ती से लागू करना है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धोनी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें झारखंड का गौरव बताया था।

अमेरिका-इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला

ईरान ने इजराइल-दुबई पर मिसाइलें दागीं, कतर-बहरीन और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक

एजेंसी, तेल अवीव/तेहरान

इजराइल ने शनिवार सुबह (भारतीय समयानुसार) ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागीं हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। दरअसल, इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है।

अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शनः इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम 'लियोनस् रोर' (शेर की दहाड़) रखा है। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रम्प के मुताबिक, अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है।

ईरान-अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल पर विवाद चल रहा थाः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में दावा- 300 की मौत, 500 घायल

एजेंसी, काबुल/इस्लामाबाद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोगों मारे गए हैं, जबकि 500 से ज्यादा घायल हुए। दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका दखल देगा? इस पर उन्होंने कहा कि मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

वहीं पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। उनका कहना है कि इन गतिविधियों के लिए अफगान तालिबान के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात हुई, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के जवाब में कार्रवाई की। इसके बाद में पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' शुरू किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार और अन्य प्रांतों में एयरस्ट्राइक की।

♦ ट्रम्प बोले- पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा, पाक का दावा- आतंकी हमलों के पीछे भारत

पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के अनुसार, अब तक 274 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। उनका कहना है कि 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट की गईं, 74 चौकियां तबाह की गईं और 18 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उसके 12 सैनिक मारे गए और 27 घायल हुए हैं। वहीं तालिबान का कहना है कि उसके सिर्फ 8 से 13 लड़ाके मारे गए और कुछ घायल हुए हैं। उसने दावा किया कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दो सैन्य मुख्यालयों समेत कई चौकियों पर कब्जा किया गया।

आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 18 लोगों की मौत

एजेंसी, अमरावती

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में शनिवार को पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाका हो गया। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के समय यूनिट में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ब्लास्ट हुआ। धमाके इतना भीषण था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भेजना शुरू किया।

राज्य की गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी करने को कहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है।

बोलिविया में करेंसी से भरा प्लेन क्रैश, 15 की मौत, 30 घायल, खराब मौसम के कारण रनवे से फिसला

एजेंसी, ला पाज

बोलिविया के एल आल्टो शहर में शनिवार सुबह (भारतीय समयानुसार) एक विमान क्रैश हो गया। यह बोलिविया की वायुसेना का हरक्यूलिस विमान था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खराब मौसम के बीच विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की व्यस्त सड़क पर जा गिरा। जिस सड़क पर यह गिरा, वहां खड़ी 10 से 15 गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गई।

एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आई। सड़क पर बैंक के नोट भी बिखरे नजर आए, जिन्हें उठाने के लिए लोग मौके पर जुट गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हादसे के बाद अफरातफरी का माहौल दिखा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि, इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

❐ चहाईवे पर बिखरे नोट उठाने जुटे लोग

हादसे के बाद एल आल्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय एयरलाइन ने बयान जारी कर बताया कि दुर्घटनाग्रस्त प्लेन उसके बेड़े का हिस्सा नहीं था, यह बोलिवियन एयर फोर्स का विमान था। स्थानीय मीडिया में प्रसारित फुटेज में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखा। हादसे के बाद प्लेन दो टुकड़ों में बंट गया। बोलिविया का सेंट्रल बैंक आज इस घटना पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है। हादसे के कारणों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है। प्रशासन ने मृतकों की पहचान और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

चरणबद्ध तरीके से जारी हुई संशोधित मतदाता सूची, नदिया में लगभग 2.71 लाख और बांकुरा में 1.18 लाख नाम घटे

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग द्वारा चरणबद्ध ढंग से प्रकाशित की जा रही संशोधित मतदाता सूचियों ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। आंकड़ों के अनुसार नदिया जिले में इस प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक लगभग 2.71 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि बांकुड़ा जिले में कुल मिलाकर करीब 1.18 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक, उत्तर कोलकाता क्षेत्र में सात विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के कब्जे में हैं, वहां पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 4.07 लाख नाम हटाए गए। इनमें से लगभग 3.90 लाख नाम प्रारूप सूची के स्तर पर हटाए गए थे, जबकि अंतिम सूची में अतिरिक्त 17 हजार नाम विलोपित किए गए। हालांकि इस क्षेत्र में नए नामों के समावेशन की अंतिम संख्या अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं की गई है।

बांकुड़ा जिले में पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत के समय कुल मतदाता संख्या 30 लाख 33 हजार 830 थी। प्रारूप सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 29 लाख एक हजार नौ रह गई। सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के अगले चरण में करीब चार हजार और नाम हटाए गए, हालांकि प्रपत्र-6 के तहत कुछ हजार नए नाम जोड़े भी गए। अंतिम सूची में अब मतदाताओं की संख्या लगभग 29.15 लाख है, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब 1.18 लाख की शुद्ध कमी को दर्शाती है।

बांग्लादेश सीमा से सटे नदिया जिले में मतदाताओं की संख्या चार नवंबर को प्रक्रिया शुरू होने के समय 44.18 लाख थी, जो घटकर अंतिम सूची में लगभग 41.45 लाख रह गई। प्रारूप सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित होने के बाद यह संख्या 42 लाख दो हजार 261 तक आ गई थी। इस प्रकार जिले में कुल मिलाकर लगभग 2.73 लाख नाम हटाए गए। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में अंतिम सूची में 11 लाख 96 हजार 651 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि यहां कुल एक लाख दो हजार 835 नाम विलोपित किए गए हैं।

शनिवार को कई जिलों में अद्यतन मतदाता सूची की हार्ड कॉपी प्रदर्शित की गई, हालांकि दोपहर तक आयोग के निर्धारित पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग पर सूची पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी थी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नाम हटाने के मुख्य कारण मृत्यु, स्थानांतरण, दोहराव और संबंधित व्यक्ति का पता न चल पाना रहे, जबकि नए नाम दस्तावेजों की जांच के बाद जोड़े गए।

आयोग के अनुसार, 16 दिसंबर को जारी प्रारूप सूची में शामिल 7.08 करोड़ मतदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है स्वीकृत, विलोपित और विचाराधीन। इससे पहले अगस्त, 2025 तक की सूची में राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ थी, जो पहले चरण की जांच में 58 लाख से अधिक नाम हटने के बाद घटकर 7.08 करोड़ रह गई थी। वर्ष 2002 के बाद यह पहली बार है जब राज्यव्यापी स्तर पर इतनी व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया संचालित की गई। इस दौरान 1.67 करोड़ मतदाताओं के मामलों में सुनवाई की गई, जिनमें 1.36 करोड़ को तार्किक विसंगतियों के कारण चिन्हित किया गया था और 31 लाख नामों का उचित मानचित्रण नहीं पाया गया था। अभी भी लगभग 60 लाख मतदाता विचाराधीन श्रेणी में हैं और निर्णय के आधार पर पूरक सूचियां चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

मराठी विश्वकोश में 1857 संग्राम को 'उठाव' लिखने पर विवाद

संशोधन की मांग को लेकर विधानमंडल में याचिका दायर

एजेंसी, नागपुर

महाराष्ट्र शासन के मराठी विश्वकोश मंडल द्वारा प्रकाशित मराठी विश्वकोश में 1857 के स्वाधीनता संग्राम को 'उठाव' (विद्रोह) के रूप में उल्लेखित किए जाने को लेकर राज्य में विवाद गहराता जा रहा है। स्वाधीनता सेनानियों के योगदान का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए पत्रकारिता, साहित्य, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्तियों ने राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष संशोधन की मांग करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 1857 का संघर्ष केवल 'उठाव' या 'विद्रोह' नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम था। इस संदर्भ में क्रांतिकारी विचारक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक '1857 चे स्वातंत्र्यसमर' का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से स्वाधीनता संग्राम बताया गया है।

♦ विधानमंडल मे संशोधन की मांग करने वाली याचिका दायर- स्वाधीनता संग्राम को 'उठाव' कहने पर दर्ज कराई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मराठी विश्वकोश के खंड-1 और खंड-18 में इस ऐतिहासिक घटना को 'अठराशे सत्तावनचा उठाव' के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर इसे 'विद्रोह' तथा अन्य जगह 'स्वाधीनता संग्राम' कहा गया है। इस प्रकार के असंगत उल्लेख को इतिहास के साथ अन्याय बताया गया है। याचिका में विशेष रूप से महान स्वाधीनता सेनानियों रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे का एकवचन में उल्लेख किए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

राहुल गांधी बोले- टीम प्लेयर बनो, वरना मैं ठीक कर दूंगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं

एजेंसी, बरनाला

पंजाब के बरनाला में शनिवार को कांग्रेस की मजदूर महारैली हुई। इसमें राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नेताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि टीम प्लेयर बनो। वरना रिजर्व में बैठा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे आप कितने भी बढ़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। नहीं बने तो मैं और खड़गे आपको ठीक कर देंगे। यहां सारे सीनियर नेता बैठे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। जो भी होगा पंजाब में इनकी रिस्पेक्ट से होगा।

उन्होंने कहा कि 4 महीने से अमेरिका-भारत डील रुकी थी। संसद में जब मेरा भाषण चल रहा था तो उसे रोका जा रहा था। उसी शाम प्रधानमंत्री का फोन ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा है। इस बात को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया है। पीएम ने ट्रंप को फोन किया। लेकिन किसी मंत्री को नहीं पूछा और कह दिया कि मैं डील के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि डील में सोयाबीन दाल, अखरोट, बादाम यह सारा अमेरिका को दे दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मोदी ने दरवाजा खोल दिया। अमेरिका का सामान आ रहा है। ट्रंप ने PM मोदी का गला पकड़ लिया है। सिर झुका दिया है। मोदी भी डील नहीं चाहते थे। चार महीने से वह रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम ब्यूरोक्रेटस से पूछते थे कि कृषि क्षेत्र तो नहीं खोल रहे हैं। वह जवाब देते थे कि नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो काम चार महीने में नहीं किया वह मोदी ने 15 मिनट में कैसे कर दिया।

खड़गे बोले- 2 मोर्चों पर बड़ी लड़ाई लड़नी हैः इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि पंजाब की धरती पर किसान और मजदूरों की महारैली हो रही है। यहां बातें किसानों के पक्ष में होंगी। जैसे आप तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़े थे। वैसे ही आप केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप को 2 मोर्चों पर बड़ी लड़ाई लड़नी है। एक तरफ मोदी सरकार तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार से लड़ना है। कांग्रेस सरकार ने जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए कई कानून लाई, लेकिन आज मोदी सरकार एक-एक करके सबकुछ बेच रही है। नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी हैं। खड़गे ने कहा कि यह ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं। वहां सिर झुका रहे हैं। नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वह करते हैं। यह देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अपने देश को गुलामी में रखने का काम कर रहे हैं। उनकी बी टीम भी उनका साथ दे रही है।

चन्नी ने कहा- केजरीवाल पंजाब को लूट रहेः जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा केजरीवाल जैसे काले अंग्रेज पंजाब को लूटने आए थे, आज वह लूटकर लेकर जा रहे हैं। आज पंजाब के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने एमएसपी की लीगल गारंटी, मनरेगा की बात कही है। आपने मुझे तीन महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। बड़े-बड़े बिजली के बिल माफ किए। हर वर्ग के लिए काम किया। राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।

बाजवा बोले- पंजाब वाले तीन चीजें चाहते हैंः नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब 2027 का फतवा कांग्रेस के हाथ में देने जा रहा है। आप महीने में एक बार पंजाब आओ। जो लोग 2029 में राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं वह हाथ खड़ा करें। हम पंजाब वाले तीन चीजें आपसे चाहते हैं। जब अपनी सरकार आए तो जो हमारी पहचान (पंजाब) जय जवान जय किसान वाली थी, मोदी ने जो धोखा किया, अग्नीवीर भर्ती शुरू कर दी, जब सरकार बने तो सेना की रैगुलर भर्ती शुरू हो। अग्नीवीर की भर्ती बंद हो। इंडो अमेरिकन एग्रीमेंट किया गया। उससे किसानों को नुकसान होगा। 1947 से लेकर जब तक मनमोहन सिंह की सरकार रही है, हमने डब्ल्यूडीयू को नहीं माना। इस डील को कैंसिल किया जाएगा।

ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025- भारत में युवाओं के मेंटल हेल्थ को लेकर चौंकाने वाला आकड़ा आया -84 देशों की स्टडी में भारतीय युवा 60वें स्थान पर,मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी चिंता-समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» डिजिटल युग,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और युवा मानसिक स्वास्थ्य- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति का समग्र विश्लेषण

» भारतीय युवाओं के मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी चिंता- प्रश्न तकनीक बनाम मानव का नहीं, बल्कि संतुलन का है,डिजिटल युग में रहकर डिजिटल अनुशासन विकसित करना ही समाधान है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव जीवन को अभूतपूर्व गति, सुविधा और वैश्विक संपर्क प्रदान किया है।ओपनएआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा विकसित एआई उपकरणों ने शिक्षा,स्वास्थ्य, वित्त, प्रशासन और व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों तक में गहरी पैठ बना ली है।भारत जैसे युवा देश में यह प्रभाव और भी व्यापक है,जहाँ डिजिटल क्रांति ने स्मार्टफोन और इंटरनेट को जनसामान्य तक पहुँचा दिया है।किंतु इसी परिवर्तनशील परिदृश्य में एक गंभीर प्रश्न उभर रहा है,क्या अत्यधिक डिजिटल निर्भरता और शॉर्ट वीडियो संस्कृति हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है?मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि भारतीय चिंतन परंपरा में कहा गया है"अति सर्वत्र वर्जयेत्।" यह केवल नैतिक उपदेश नहीं,बल्कि संतुलित जीवन का वैज्ञानिक सिद्धांत है।इसका भावार्थ है जब तकनीक, साधन से अधिक उद्देश्य बन जाती है, तब उसके दुष्प्रभाव स्पष्ट होने लगते हैं।हाल ही में 26 फरवरी 2026 को जर्मनी से जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 ने इसी चिंता को तथ्यात्मक आधार दिया है।यह रिपोर्ट स्पेन लेबस के ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार की गई है। विश्व के 84 देशों के 10 लाख से अधिकप्रतिभागियों के डेटा पर आधारित इस अध्ययन में 78,093 भारतीयों को शामिल किया गया,जिनमें 29,594 प्रतिभागी 18-34 वर्ष आयु वर्ग के थे और 24,088 प्रतिभागी 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष के भारतीय युवा मानसिक स्वास्थ्य के मानकों पर 84 देशों में 60वें स्थान पर हैं। उनका माइंड हेल्थ क्वोशेंट स्कोर मात्र 33 दर्ज किया गया, जबकि 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का स्कोर 96 रहा और वे वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर रहे। यह पीढ़ीगत अंतर केवल सांख्यिकीय नहीं,बल्कि सामाजिक संरचना में गहरे परिवर्तन का संकेत है।यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लागू किया था,जोमानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा करता है। परंतु जमीनी स्तर पर जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है। मनोचिकित्सकों की उपलब्धता प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या अपर्याप्त है।भारत यदि इस चुनौती को गंभीरता से लेकर समग्र रणनीति अपनाता है, तो भविष्य में वैश्विक रैंकिंग में सुधार संभव है। मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत सुख- शांति का विषय नहीं,बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना और प्रगति का आधार है। इसलिए 2025 की यह रिपोर्ट केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि नीति-निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं,सभी के लिए एक साझा आह्वान है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए और स्वस्थ, संतुलित तथा सशक्त युवा पीढ़ी का सटीकता से निर्माण किया जाए। साथियों बात अगर हम एमएचक्यू स्कोर को समझने की करें तो यह एक समग्र सूचकांक है,जो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता,सामाजिक अनुकूलन, ध्यान क्षमता, आत्मनियंत्रण, तनाव से उबरने की क्षमता और जीवन प्रबंधन कौशल को मापता है।जब युवा वर्ग का स्कोर बुजुर्गों की तुलना में लगभग एक-तिहाई रह जाता है, तो यह स्पष्ट करता है कि नई पीढ़ी केवल चिंता या अवसाद से ही नहीं जूझ रही,बल्कि उसकी मूल मनोवैज्ञानिक क्षमताएँ भी कमजोर पड़ रही हैं।रिपोर्ट की प्रमुख वैज्ञानिक और संस्थापक ने स्पष्ट कहा है कि समस्या केवल डिप्रेशन या एंग्जायटी तक सीमित नहीं है;युवाओं में भावनाओं को नियंत्रित करने, ध्यान केंद्रित रखने, स्थिर रिश्ते बनाने और तनाव से उबरने की आधारभूत क्षमता प्रभावित हो रही है। साथियों बात अगर हम डिजिटल एक्सपोज़र इस गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है इसको समझने की करें तो,भारत में पहली बार स्मार्टफोन उपयोग की औसत आयु 16.5 वर्ष दर्ज की गई है।किशोरावस्थामस्तिष्क विकास का संवेदनशील चरण होता है,जहाँ न्यूरल नेटवर्क तेजी से विकसित होते हैं। ऐसे समय में निरंतर शॉर्ट वीडियो,रील्स और त्वरित डोपामिन आधारित कंटेंट मस्तिष्क को तत्काल संतुष्टि का आदी बना देता है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 98 हजार लोगों पर किए गए 71 अध्ययनों के विश्लेषण में पाया गया कि अत्यधिक शॉर्ट वीडियो देखने से ध्यान क्षमता घटती है, आत्मनियंत्रण कम होता है और तनाव व चिंता बढ़ सकती है। हर कुछ सेकंड में बदलता दृश्य और ध्वनि उत्तेजना मस्तिष्क की प्राकृतिक एकाग्रता प्रणाली को बाधित करती है, जिससे पढ़ाई, शोध, पुस्तक पठन और गहन चिंतन जैसे कार्य कठिन प्रतीत होने लगते हैं। भारत स्मार्टफोन एक्सपोज़र के मामले में 84 देशों में 71वें स्थान पर है, किंतु यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि इंटरनेट उपयोग करने वाले 18-34 आयु वर्ग के वैश्विक 41 प्रतिशत युवा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है; विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के युवा इससे जूझ रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, इस अध्ययन में घाना प्रथम स्थान पर रहा, जबकि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला फिनलैंड 18–34 आयु वर्ग में 40वें स्थान पर रहा। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक समृद्धि मानसिक स्वास्थ्य की बिलकुल गारंटी नहीं है। साथियों बात अगर हम रिपोर्ट में खानपान को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है इसको समझने की करें तो,18-34 वर्ष के 44 प्रतिशत भारतीय युवा नियमित रूप से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं,जबकि 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में यह आंकड़ा केवल 11 प्रतिशत है। पिछले 15 वर्षों में भारत अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के लिए विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल हुआ है।उच्च शर्करा,सोडियम और कृत्रिम तत्वों से भरपूर भोजन केवल मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आंत-मस्तिष्क अक्ष को प्रभावित कर मानसिक असंतुलन की संभावना भी बढ़ाते हैं।वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है; संतुलित आहार भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। पारिवारिक जुड़ाव इस परिदृश्य में सुरक्षा कवच की भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार 18-34 आयु वर्ग के 64 प्रतिशत युवाओं ने स्वयं को परिवार के निकट बताया,जबकि 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में यह आंकड़ा 78 प्रतिशत रहा। पारिवारिक करीबी के मामले में भारत दोनों आयु वर्गों में 28वें स्थान पर है। भारतीय समाज की पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था,आध्यात्मिकता और सामुदायिक संस्कृति अभी भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है, किंतु नगरीकरण, प्रवासन और डिजिटल जीवन शैली के कारण इसमें भीगिरावट देखी जा रही है। जब सामाजिक समर्थन तंत्र कमजोर होता है, तो व्यक्ति का भावनात्मक प्रतिरोधक तंत्र भी कमजोर पड़ता है। साथियों अब हमें यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी स्वयं समस्या नहीं है;उसका अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग समस्या बनता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा में वैयक्तिकृत शिक्षण, स्वास्थ्य में रोग निदान, कृषि में उत्पादकता वृद्धि और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकती है। किंतु यदि हर निर्णय, हर प्रश्न और हरजिज्ञासा का उत्तर केवल एआई से प्राप्त किया जाए, तो मानव मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक औरसृजनात्मक क्षमता कुंठित हो सकती है। जब बच्चे और युवा बिना स्वयं विचार किए समाधान खोजने लगते हैं, तो उनका तार्किक कौशल और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। तकनीक सहायक बने, विकल्प नहीं,यह सिद्धांत अपनाना आवश्यक है।वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो विकसित देशों के युवा भी मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं। आर्थिक प्रगति, प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली, नौकरी का दबाव और सामाजिक तुलना ने युवाओं पर अदृश्य मानसिक बोझ डाला है। सोशल मीडिया पर आदर्श जीवनशैली का प्रदर्शन आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। निरंतर तुलना की संस्कृति व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह पर्याप्त नहीं है। इससे आत्ममूल्यांकन नकारात्मक होता है और चिंता बढ़ती है। इस संदर्भ में डिजिटल साक्षरता केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं,बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जागरूकता तक विस्तारित होनी चाहिए। साथियों बात अगर हम भारत के लिए यह रिपोर्टचेतावनी के साथ अवसर भी प्रस्तुत करती है इसको समझने की करें तो, एक ओर युवा आबादी देश की जनसांख्यिकीय शक्ति है,दूसरी ओर यदि उनकी मानसिक सेहत कमजोर होती है तो उत्पादकता, नवाचार और सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। नीति-निर्माताओं को स्कूल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल उपयोग की समय- सीमा, खेल-कूद और कला गतिविधियों को प्रोत्साहन, तथा पोषण संबंधी जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवारों को भी संवाद, साझा समय और डिजिटल डिटॉक्स जैसे उपाय अपनाने होंगे।कानूनी दृष्टि से यह रिपोर्ट कोई औपचारिक सरकारी नीति दस्तावेज नहीं है,बल्कि शोध- आधारित सार्वजनिक रिपोर्ट है। इसकी वैज्ञानिक मान्यता पर विशेषज्ञों के बीच मतभेद हो सकते हैं; कुछ इसे व्यापक और उपयोगी डेटा-संग्रह मानते हैं, तो कुछ इसकी पद्धति पर प्रश्न उठाते हैं। फिर भी, इतने बड़े वैश्विक नमूने पर आधारित निष्कर्षों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीति निर्माण में इसे संकेतक के रूप में लिया जा सकता है, न कि अंतिम सत्य के रूप में। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि प्रश्न तकनीक बनाम मानव का नहीं,बल्कि संतुलन का है। डिजिटल युग में रहकर डिजिटल अनुशासन विकसित करना ही समाधान है। यदि युवा वर्ग समय-प्रबंधन,आत्मनियंत्रण, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पारिवारिक संवाद को प्राथमिकता दे,तो तकनीक उनके विकास का साधन बन सकती है। समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और सरकार सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता की पूरक बने, प्रतिस्थापक नहीं।"अति सर्वत्र वर्जयेत्" का शाश्वत संदेश आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। डिजिटल क्रांति मानव सभ्यता की उपलब्धि है, किंतु मानसिक संतुलन और मानवीय संबंध ही उसके स्थायी आधार हैं। यदि हम संतुलन, संयम और विवेक के साथ तकनीक का उपयोग करें, तो युवा पीढ़ी न केवल मानसिक रूप से सशक्त होगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अग्रणी बनेगी। यही इस वैश्विक रिपोर्ट का मूल संदेश और भारत के लिए मार्गदर्शन है।

-संकलनकर्ता लेखक
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार
साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक
चिंतक कवि संगीत माध्यमा
सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन
सनमुखदास भावनानी गोंदिया
महाराष्ट्र 9284141425

बदलते रिश्तों का सच

लेखक - कांतिलाल मांडोत

दिल्ली की एक पारिवारिक अदालत का दृश्य आज के शहरी भारत की बदलती सामाजिक तस्वीर को बयान करता है। सुबह के दस बजे हैं। एक युवा महिला, जिसकी उम्र मुश्किल से तीस के आसपास होगी, शांत चेहरे के साथ न्यायालय की बेंच पर बैठी है। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय का संतुलन दिखाई देता है। तीन वर्ष पहले इसी महिला का विवाह पूरे उत्साह और परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ हुआ था, किंतु आज वह अपने वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए उपस्थित है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की कहानी है जिनके रिश्ते समय, अपेक्षाओं और बदलती सामाजिक संरचना के दबाव में टूट रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े संकेत देते हैं कि पिछले दो दशकों में वैवाहिक विच्छेद के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां दो दशक पहले विवाहित महिलाओं में अलगाव या विवाह विच्छेद का प्रतिशत लगभग 0.6 था, वहीं अब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों में ऐसे मामलों का अनुपात बढ़ा है। यद्यपि भारत की कुल दर अभी भी कई देशों की तुलना में कम है, परंतु महानगरों में पिछले तीन वर्षों में मामलों की संख्या तीन गुना तक बढ़ने की बात विभिन्न शोध रिपोर्टों में सामने आई है। औसतन महिलाओं की आयु लगभग 31 वर्ष और पुरुषों की 36 वर्ष बताई जाती है जब वे वैवाहिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। भारतीय समाज में 'तलाक' शब्द मूलतः विदेशी पृष्ठभूमि से आया हुआ माना जाता है। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में विवाह को एक अटूट संस्कार के रूप में देखा गया है, जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का संबंध होता था। प्राचीन ग्रंथों में विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा गया है। यही कारण है कि लंबे समय तक विवाह विच्छेद की अवधारणा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं थी। हालांकि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कुछ समुदायों में अलगाव की परंपराएं थीं, परंतु व्यापक रूप से समाज ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया। आधुनिक विधिक व्यवस्था के आने के बाद विवाह को समाप्त करने की स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया स्थापित हुई, जिसने व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण दिया। आज के समय में वैवाहिक विच्छेद के प्रमुख कारणों में क्रूरता, घरेलू हिंसा, लगातार विवाद, परित्याग, विवाह पूर्व छल, अविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 23 प्रतिशत मामलों में क्रूरता और 14 प्रतिशत में घरेलू हिंसा प्रमुख कारण के रूप में सामने आती है। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता ने विशेषकर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाया है। पहले जहां अधिकांश मामलों में पहल पुरुषों द्वारा की जाती थी, वहीं अब लगभग 58 प्रतिशत मामलों में महिलाएं स्वयं याचिका दायर कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल वैवाहिक असंतोष का संकेत नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में हो रहे व्यापक बदलावों का द्योतक है। महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में जीवनशैली, पेशेगत दबाव और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का प्रभाव दांपत्य जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है। संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी दंपतियों को अधिक स्वतंत्र तो बनाया है, किंतु सहारा देने वाली पारिवारिक संरचना कमजोर हुई है। कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि विवाह के पहले तीन वर्षों में संबंध टूटने की संभावना अधिक रहती है। इस अवधि में अपेक्षाओं का टकराव, आर्थिक समायोजन और व्यक्तित्व भिन्नताएं तीव्र रूप में सामने आती हैं। वैश्विक तुलना करें तो मालदीव, रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों में विवाह विच्छेद की दर भारत से कहीं अधिक है। भारत में यह अभी भी एक प्रतिशत से कम बताई जाती है, जो दर्शाती है कि यहां विवाह संस्था अब भी अपेक्षाकृत मजबूत है।

आबकारी नीति मामले में आप नेताओं का बरी होना बड़ी संजीवनी

लेखक-ईएमएस/ललित गर्ग

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित आबकारी नीति प्रकरण में आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा अन्य आरोपितों को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय समकालीन राजनीतिक और विधिक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अर्थात सीबीआई द्वारा पंजीकृत किया गया था और लंबे समय से सार्वजनिक बहस के केंद्र में था। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप ठोस साक्ष्यों और विश्वसनीय गवाहियों पर आधारित नहीं हैं तथा आरोपपत्र में वर्णित दावे न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। न्यायालय की यह टिप्पणी कि अनुमानों और अटकलों को विधिसम्मत प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, न केवल इस विशेष प्रकरण बल्कि समग्र अन्वेषण प्रक्रिया के लिए भी गंभीर संकेत देती है। आबकारी नीति मामले यह फैसला आप के लिए एक बड़ी संजीवनी या 'प्राणवायु'के समान है। यह फैसला आप को 'कट्टर ईमानदार' की छवि वापस पाने और आगामी चुनावों के लिए एक आक्रामक रुख अपनाने में मदद करेगा, जिससे विपक्षी दलों का मनोबल भी बढ़ा है। कोर्ट से मिली क्लीन चिट ने आप नेताओं की साख बहाल की है जिससे पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यह निर्णय 'राजनीतिक प्रतिशोध' के नैरेटिव को बल देता है जिससे आप अपनी छवि को बेदाग साबित कर पा रही है। विपक्षी दल इस घटना को केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई एवं ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक जीत के रूप में देख रहे हैं जिससे उन्हें केंद्र के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस फैसले से दिल्ली और पंजाब में आप को मजबूती मिलेगी और वह आगामी चुनावों के लिए आक्रामक प्रचार कर सकती है। विवाद का मूल वर्ष 2021 में लागू की गई नई आबकारी नीति से जुड़ा था। उस समय दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि शराब व्यापार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से राजस्व में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। किंतु नीति के क्रियान्वयन के बाद उस पर अनियमितताओं तथा कथित पक्षपात के आरोप लगाए गए। यही आरोप आगे चलकर आपराधिक प्रकरण का आधार बने। जुलाई 2022 से यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय बन गया और चुनावी सभाओं में इसे व्यापक रूप से उठाया गया। अब जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों को अपर्याप्त पाया है, तो स्वाभाविक है कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय, में चुनौती देने की घोषणा की है। अतः अंतिम विधिक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं मानी जा सकती। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात ईडी ने यह कहा है कि उससे संबंधित धनशोधन प्रकरण की जांच स्वतंत्र आधारों पर चल रही है। यदि उच्च न्यायालय भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि समान घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न अन्वेषणों की विधिक संगति किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्वेषण एजेंसियों की भूमिका अत्यंत संवेदनशील होती है। वे केवल अपराध की जांच ही नहीं करतीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। यदि न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि जांच पूर्वनिर्धारित दिशा में चलती प्रतीत होती है या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत शुचिता पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। न्याय का मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष विधिसम्मत प्रमाणों के आधार पर सिद्ध न हो जाए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शासन की समग्र विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो कठोर दंड आवश्यक है; किंतु यदि आरोप पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में टिक नहीं पाते, तो इससे राजनीतिक विमर्श की विश्वसनीयता पर भी आघात पहुँचता है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, किंतु आरोपों का उपयोग यदि मुख्यतः चुनावी रणनीति के रूप में किया जाता है और वे न्यायालय में प्रमाणित नहीं हो पाते, तो इससे जनता के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। इस निर्णय के बाद स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी को नैतिक बल प्राप्त हुआ है। किंतु इस तथ्य को केवल किसी एक दल की विजय या पराजय के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इससे व्यापक स्तर पर यह संदेश भी जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र है और वह अभियोजन की कमजोरी को रेखांकित करने से संकोच नहीं करती। न्यायालय की कठोर टिप्पणियाँ यह संकेत देती हैं कि केवल आरोपों की गंभीरता पर्याप्त नहीं है; उन्हें प्रमाणों की दृढ़ता से पुष्ट करना भी अनिवार्य है। दूसरी ओर, यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि वास्तव में किसी नीति में अनियमितता हुई थी, तो उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं किए जा सके। क्या अन्वेषण प्रक्रिया में तकनीकी कमियाँ रहीं? क्या साक्ष्य-संग्रह में सावधानी का अभाव था? या फिर आरोपों का प्रारूपण ही पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? ये प्रश्न केवल इस प्रकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य की जांच प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। भ्रष्टाचार-निरोध की दिशा में प्रभावी कदम तभी संभव हैं जब अन्वेषण निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत हो। राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार-विरोध का नैतिक आग्रह तभी प्रभावी है जब वह स्वयं प्रमाण-आधारित हो। यदि आरोपों का आधार कमजोर होगा, तो वे न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं पाएंगे और इससे वास्तविक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष भी कमजोर पड़ेगा। इस घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है-अन्वेषण एजेंसियों की स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन। लोकतंत्र में एजेंसियों को स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु वह स्वतंत्रता विधिक मानकों और न्यायिक नियंत्रण के अधीन रहती है। न्यायालय की टिप्पणियाँ यह संकेत देती हैं कि प्रक्रिया की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यदि अभियोजन पक्ष पर्याप्त तैयारी के बिना आरोप प्रस्तुत करता है, तो उसका परिणाम यही होगा कि मामला प्रारंभिक चरण में ही कमजोर पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर यह प्रकरण हमें यह स्मरण कराता है कि कानून का शासन केवल दंड देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि न्यायसंगत प्रक्रिया की गारंटी भी है। आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य पर होती है और वह भी संदेह से परे प्रमाणों के आधार पर। यदि यह मानक पूरा नहीं होता, तो किसी भी व्यक्ति को केवल सार्वजनिक धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस निर्णय का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो-क्योंकि उच्च न्यायालय में चुनौती लंबित है फिर भी यह अवसर अवश्य प्रदान करता है कि हम भ्रष्टाचार-निरोध की अपनी कार्ययोजना को अधिक सुदृढ़ और प्रमाण-आधारित बनाएं। राजनीतिक विमर्श को आरोपों की तीव्रता से आगे बढ़कर प्रमाणों की गुणवत्ता पर केंद्रित करना होगा।

खामोशी से जान लेती सेक्सवर्धक दवाएं

लेखक -डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत जैसे समाज में यौन स्वास्थ्य आज भी खुली बातचीत का विषय नहीं है। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर हाल में "सक्षम" रहें—चाहे उम्र, तनाव या बीमारी कुछ भी हो। इसी दबाव में डॉक्टर से सलाह लेना कमजोरी मान लिया जाता है, जबकि बिना जांच दवा खाना "समाधान" समझ लिया जाता है। यही चुप्पी सबसे खतरनाक है। लोग अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करते हैं, मानसिक तनाव को दबाते हैं और सामाजिक छवि बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं। नतीजा यह होता है कि एक अस्थायी समाधान स्थायी मौत में बदल जाता है। यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक असफलता है। भारत में समय-समय पर सामने आने वाली कुछ मौतें सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन उनसे जुड़ी असहज सच्चाइयों पर समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। होटल के कमरों, निजी फ्लैटों और बंद दरवाजों के पीछे हुई मौतों को "संदिग्ध परिस्थितियों" कहकर दर्ज कर दिया जाता है और मामला यहीं खत्म मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी घटनाएं अपवाद नहीं हैं। ये उस समस्या का संकेत हैं, जो देशभर में फैल चुकी है और जिसकी कीमत हज़ारों लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं—बिना चिकित्सकीय सलाह के सेक्सवर्धक दवाओं के बेतहाशा और लापरवाह इस्तेमाल से। देश में इन दवाओं की उपलब्धता किसी सामान्य टॉनिक की तरह है। मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अनधिकृत चैनलों से ये दवाएं बिना पर्ची, बिना चेतावनी और बिना किसी परामर्श के मिल जाती हैं। न उम्र पूछी जाती है, न पहले से मौजूद बीमारियों का जिक्र होता है, न ही संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाती है। मानो यह दवा नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव से निकलने का कोई आसान रास्ता हो। यही आसान रास्ता कई बार सीधे मौत की ओर ले जाता है। इन दवाओं का असर केवल शारीरिक नहीं होता। हृदय गति, रक्तचाप और नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है, खासकर तब जब पहले से हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अत्यधिक तनाव मौजूद हो। इसके बावजूद इन दवाओं के विज्ञापन मर्दानगी को चुनौती की तरह पेश करते हैं—उम्र को मात देने, क्षमता साबित करने और कमजोरी छिपाने के संदेश खुलेआम परोसे जाते हैं। सवाल यह है कि जब नतीजे जानलेवा हो सकते हैं, तो इस प्रचार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इस पूरे संकट की जड़ में समाज की वही पुरानी सोच है, जो यौन स्वास्थ्य को आज भी शर्म और चुप्पी के दायरे में रखती है। पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर हाल में सक्षम रहें, चाहे शरीर साथ दे या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना कमजोरी समझा जाता है, जबकि बिना जांच दवा लेना बहादुरी या समझदारी मान लिया जाता है। यही मानसिक दबाव व्यक्ति को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है, जिनकी कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसी मौतों के बाद भी सच्चाई अक्सर सामने नहीं आती। परिवार सामाजिक बदनामी के डर से चुप रहना बेहतर समझता है। मृत्यु प्रमाण-पत्र पर कारण कुछ और लिख दिया जाता है और मामला खत्म हो जाता है। पुलिस के लिए यह एक और "प्राकृतिक मौत" बन जाती है और सिस्टम आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर बार जब सच्चाई दबा दी जाती है, तब अगली मौत की जमीन तैयार हो जाती है। यह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक त्रासदी नहीं है। यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिसे स्वीकार करने से हम लगातार बचते रहे हैं। अगर सच सामने आए, अगर आंकड़े ईमानदारी से इकट्ठा किए जाएं, तो शायद यह साफ दिखे कि ऐसी मौतें सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से अधिकांश कभी चर्चा का विषय नहीं बनतीं। सरकार और स्वास्थ्य तंत्र की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। आखिर इन दवाओं की बिक्री पर सख्त नियंत्रण क्यों नहीं है? पर्ची को अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता? भ्रामक और आक्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब किसी दवा के दुष्प्रभाव जानलेवा हो सकते हैं, तो उसके प्रचार और उपलब्धता पर वही सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती, जो अन्य खतरनाक पदार्थों पर होती है? हर घटना के बाद "जांच जारी है" कह देना अब पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि जांच के नतीजों से नीति क्यों नहीं बनती।

धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड का नोटिस

- रेजिडेंशियल प्लॉट पर पैथोलॉजी लैब चलाने का आरोप, 15 दिन में मांगा जवाब

रांची (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। मामला रांची के हरमू इलाके में स्थित ॥-10 आवासीय प्लॉट से जुड़ा है। बोर्ड का आरोप है कि यह प्लॉट केवल आवासीय उद्देश्य से आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान में वहां कथित तौर पर एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। नोटिस में धोनी से इस

संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्लॉट का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। बोर्ड की कार्रवाई तेज, पहले भी शुरू हुई है जांच सूत्रों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड ने हाल के दिनों में ऐसे कई मामलों की समीक्षा शुरू की है, जिनमें आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई चर्चित हस्ती। बोर्ड का उद्देश्य आवंटन की शर्तों को सख्ती से लागू करना है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धोनी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें झारखंड का गौरव बताया था।

रिंकू सिंह अलीगढ़ से कोलकाता रवाना

- टीम इंडिया से जुड़ेंगे, रिश्तेदारों से बोले- मां का ख्याल रखना, भाई ने पिता की अस्थियां विसर्जित कीं

अलीगढ़ (एजेंसी)। क्रिकेटर रिंकू सिंह शनिवार को अलीगढ़ से कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मीडिया को बताया था कि रिंकू शनिवार को टीम में शामिल हो रहे हैं। दरअसल, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच एक वर्चुअल नॉकआउट है, जिसमें जीतने वाली टीम ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका के साथ

आज भारत-वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला

- मौसम बड़े मुकाबले में खलल डाल सकती है
- जो जीता वो सेमीफाइनल में

कोलकाता (एजेंसी)। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च को कोलकाता में होने वाला मुकाबला सेमीफाइनल की दृष्टि से बेहद अहम है। यह मैच किसी क्वार्टरफाइनल से कम नहीं माना जा रहा। दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है, लेकिन फैंस के मन में एक सवाल है-क्या बारिश इस बड़े मुकाबले में खलल डाल सकती है? भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच रविवार, 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा।

सेमीफाइनल के लिए 'करो या मरो' मुकाबला- भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रन से जीत दर्ज कर अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। अब टीम इंडिया को शाई होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज टीम को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का करना होगा। वहीं, विंडीज भी जीत के साथ टॉप-4 में जगह बना सकती है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च को कोलकाता में बारिश की संभावना नहीं है। मैच के दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद है।दिन में तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि शाम को

यह घटकर 25-26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल मौसम पूरी तरह से क्रिकेट के अनुकूल नजर आ रहा है और फैंस को पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है।

अगर बारिश हुई तो क्या होगा?

हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन अगर किसी कारणवश मैच रद्द होता है तो समीकरण बदल

जाएंगे। भारत और वेस्टइंडीज दोनों के पास फिलहाल 2-2 अंक हैं। मैच रद्द होने पर दोनों को एक-एक अंक मिलेगा और तीन-तीन अंक हो जाएंगे।ऐसी स्थिति में बेहतर नेट रन रेट के आधार पर वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर 67 साल में पहली बार रणजी चैंपियन बना

- फाइनल मैच ड्रॉ रहा, कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत तय हुई

हुबली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम 1959 से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और 67 साल बाद पहला खिताब जीता है। इस जीत पर जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने टीम को 2 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। बेंगलुरु के पास हुवली क्रिकेट ग्राउंड पर 5 दिन मैच में 24 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 584 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक को 293 रन पर ऑल आउट कर दिया था।

दूसरी पारी में जम्मू कश्मीर ने 4 विकेट पर 342 रन बनाए और पारी डिक्लेयर कर दी। पहली पारी में मिली बढ़त की आधार पर जम्मू कश्मीर की टीम को विजेता घोषित किया गया। टीम ने 8 बार की विजेता कर्नाटक को हराया है।

5वें दिन कामरान-साहिल के शतक- जम्मू-कश्मीर ने 5वें और आखिरी दिन 186/4 के स्कोर से खेलना शुरू किया। कामरान इकबाल (160) और साहिल लोत्रा (101) ने नाबाद

शतक लगाया। टीम ने लंच के बाद लंच सेशन के बाद 342/4 को स्कोर पर दूसरी पारी डिक्लेयर कर दी, इसी को साथ मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया। शुक्रवार को मुकाबले के चौथे दिन टीम ने 4 विकेट गंवा दिए। यावर हसन 1, शुभम पुंदीर 4, कप्तान पारस डोगरा 16 और अब्दुल समद 32 रन बनाकर आउट हुए। कर्नाटक से प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट ले चुके हैं। विजयकुमार वैशाख और श्रेयस गोपाल को 1-1 विकेट मिला।

पहली पारी में शुभम पुंदीर का शतक- गुरुवार को मुकाबले के पहले दिन जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर बैटिंग चुन ली। यावर हसन ने 88, शुभम पुंदीर ने 121, कप्तान पारस डोगरा ने 70, अब्दुल समद ने 61, विकेटकीपर कन्हैया वाधवान ने 70 और साहिल लोत्रा ने 72 रन बनाकर टीम को 584 तक पहुंचा दिया।

जम्मू कश्मीर ने ढाई दिन बैटिंग की और कर्नाटक के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। होम टीम के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लिए। विद्याधर पाटील, विजयकुमार वैशाख, श्रेयस गोपाल और शिखर शेट्टी ने 1-1 विकेट लिया।

चैंपियंस लीग फुटबॉल- राउंड ऑफ 16 का शेड्यूल

- 15 बार की विजेता रियल मैड्रिड से भिड़ेगी मैनचेस्टर सिटी
- लिवरपूल-आर्सनल के सामने भी मजबूत चुनौती

मैनचेस्टर सिटी (एजेंसी)। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच अब तक 15 मैच खेले गए। दोनों को 5-5 में जीत मिली, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ भी रहे।

यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट ईएफए चैंपियंस लीग (सीएल) के राउंड-ऑफ-16 के ड्रॉ निकल चुके हैं। इंग्लैंड की मैनचेस्टर सिटी और रिकॉर्ड 15 बार की विजेता रियल मैड्रिड एक बार फिर आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच भी माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें टाइटल जीतने की दावेदार हैं। कोच पेप ग्वार्डिओला की मैनचेस्टर सिटी और कार्लो एंसेलोटी की रियल मैड्रिड के बीच पिछले कुछ सालों में एक नई राइवलरी पैदा हो गई है। पिछले सीजन भी दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए थे। फुटबॉल फैंस भी सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं।

व्यापार

हरित इस्पात अनिवार्य करने से 2030 तक 1.6 करोड़ टन मांग संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी परियोजनाओं में हरित इस्पात का इस्तेमाल 26 प्रतिशत तक अनिवार्य करने से 2030 तक 1.6 करोड़ टन तक ग्रीन स्टील की मांग बढ़ सकती है। इससे एक तरफ जहां कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट में यह कहा गया। सीआईआई-ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा विकसित और क्लाइमेट कैटालिस्ट द्वारा समर्थित उद्योग तत्परता आकलन रिपोर्ट में पाया गया है कि हरित इस्पात को अनिवार्य किये जाने पर देश हरित इस्पात की सार्वजनिक खरीद (जीपीपी) व्यवस्था को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कदम से वित्त वर्ष 2027-28 से प्रमाणित निम्न-कार्बन इस्पात के लिए देश का पहला बड़े पैमाने पर, सुनिश्चित बाजार बनाने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक खरीद पर प्रतिवर्ष लगभग 45 से 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सरकारी परियोजनाओं में लगभग 3.16 करोड़ टन स्टील की खपत होती है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग सात करोड़ टन कार्बन (सीओ2) उत्सर्जन हुआ। अध्ययन के अनुसार, यदि केवल 26 प्रतिशत का मामूली अनिवार्य लक्ष्य भी तय किया जाए तो वित्त वर्ष 2029-30 तक प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात उत्पादकों से 1.6 करोड़ टन प्रमाणित ग्रीन स्टील की मांग उत्पन्न हो सकती है। इससे देश में उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने में मदद मिलेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता भी मजबूत होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर यह लक्ष्य और बढ़ाकर 37 प्रतिशत रखा जाए तो मांग 2.4 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। इससे 2030 तक 2.97 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। सीआईआई के कार्यकारी निदेशक और ग्लोबल इकोलेबलिंग नेटवर्क बोर्ड के चेयरमैन के.एस. वेंकटगिरी ने कहा, हरित सार्वजनिक खरीद नीति से भारत के इस्पात उद्योग को कम-कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादन की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, बाजार में हरित इस्पात को बढ़ावा मिलेगा और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा, यह नीति इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धा भी मजबूत करेगी और भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। क्लाइमेट कैटलिस्ट की निदेशक साक्षी बलानी ने कहा, यह अध्ययन एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि अगर सरकार हरित इस्पात के इस्तेमाल का एक स्पष्ट नियम बना दे, तो देश का इस्पात क्षेत्र किसी भी सरकारी सब्सिडी या नई प्रौद्योगिकी से कहीं ज्यादा तेजी से बदल सकता है।

गोल्ड की तेज रफ्तार, 1,800 उछला सोना, चांदी 2,500 रुपए सस्ती

नईदिल्ली, एजेंसी। आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपए बढ़कर 1,64,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बृहस्पतिवार को 1,62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच सोने की कीमत बढ़ी। बाजार में बढ़ते अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद और स्थिर डॉलर के मुकाबले पश्चिम एशिया में लगातार तनाव का असर है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक टकराव और शुल्क से जुड़ी अनिश्चितता ने सुरक्षित निवेश की मांग को जारी रखा। हालांकि, सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही, और यह 2,70,500 रुपए प्रति किलोग्राम के पिछले बंद भाव से 2,500 रुपए यानी लगभग एक प्रतिशत टूटकर 2,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 1.42 डॉलर यानी 1.6 प्रतिशत बढ़कर 89.72 डॉलर प्रति औंस रही। हालांकि, सोना थोड़ा घटकर 5,172.17 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ गिरफ्तार

शेयर बाजार में लिस्टेड है कंपनी

नईदिल्ली, एजेंसी। फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ ऋषि गुप्ता को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

शेयर बाजार में लिस्टेड-फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ ऋषि गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

क्या कहा बैंक ने- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिस्टिंग नियमों के विनियम 30 के तहत एक एक्सचेंज डिस्क्लोजर में बैंक ने स्पष्ट किया कि यह जांच एक व्यापारिक साझेदार से संबंधित है और इसका उसके अपने जीएसटी अनुपालन से कोई संबंध नहीं है। बैंक ने कहा कि वह स्थिति से निपटने और

उससे उबरने के लिए सक्रिय रूप से उचित कदम उठा रहा है। बैंक ने आगे बताया कि मुख्य वित्तीय अधिकारी केतन मर्चेंट को संगठन का नेतृत्व करने और दैनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक की मंजूरी- हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर 2023 अवधि में इसके लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा भुगतान बैंक जो निवासियों द्वारा नियंत्रित हैं और जिन्होंने पांच साल का परिचालन पूरा कर लिया है,

बिकवाली मोड में है शेयर

फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह बिकवाली मोड में है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बैंक के शेयर की कीमत में7.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह शेयर शुक्रवार को 192.45 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 209 रुपये से 182.90 रुपये के बीच था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 339 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 180.50 रुपये है।

कैसे रहे दिसंबर तिमाही के नतीजे

दिसंबर तिमाही में फिनो पेमेंट्स बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत बढ़कर 22.8 करोड़ से 23.1 करोड़ हो गया। तिमाही आधार पर मुनाफे में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 21.15 करोड़ था। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में पिछले वर्ष की तुलना में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.7 करोड़ तक पहुंच गई।

वहीं, फिनो पेमेंट्स बैंक के राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 461.3 करोड़ तक पहुंच गया। राजस्व वृद्धि का मुख्य कारण इसके डिजिटल भुगतान व्यवसाय में मजबूत वृद्धि थी, जिसने कुल राजस्व में 24 प्रतिशत का योगदान दिया। एबिटा में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 60.2 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर तिमाही के दौरान बैंक के ग्राहकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.34 करोड़ तक पहुंच गई। इस तिमाही में 8.3 लाख नए खाते खोले गए, जिनमें 70,000 से अधिक डिजिटल खाते शामिल हैं।

भारत बायोटेक इंटरनेशनल अब शेयर बाजार में होगी लिस्ट

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड 500 मिलियन डॉलर का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। साल 1996 में स्थापित कंपनी भारत बायोटेक को कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक पहचान मिली थी, जब उसने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर सुर्खियां बटोरीं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी-भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्ट होने की योजना बना रही है। यह कंपनी 500 मिलियन डॉलर का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस संबंध में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इश्यू का साइज, स्ट्रक्चर और समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है। वहीं, कंपनी की ओर से भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और बाजार की परिस्थितियों तथा निवेशकों की रुचि के आधार पर प्रस्ताव में बदलाव संभव है।

कंपनी लिस्टिंग की तैयारी ऐसे समय में कर रही है जब भारतीय प्राथमिक बाजार रिकॉर्ड फंड जुटाने के बाद अब अधिक सतर्क रुख में है। शेयर बाजार की बिकवाली के बीच हेल्थकेयर और फार्मा

क्षेत्र में निवेशकों की लॉन्ग टर्म रुचि बनी हुई है। हालांकि, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की सावधानी के कारण बड़ी कंपनियों के लिए मूल्य निर्धारण और सही समय का चयन महत्वपूर्ण हो गया है।

क्या है कंपनी का प्लान

भारत बायोटेक आईपीओ से जुटाई गई रकम का उपयोग कंपनी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के विस्तार में करेगी। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग कैपिसिटी बढ़ाने और अगली पीढ़ी के टीकों, बायोलॉजिक्स के विकास में भी पैसे खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बाजार में उतरने के साथ भारत बायोटेक को अधिक खुलासे, तिमाही नतीजों की समीक्षा और निवेशकों की कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है।

आईपीओ मार्केट में आ सकता है उछाल- इस साल आईपीओ के बाजार में 32 प्रतिशत की तेज वृद्धि हो सकती है और कुल इश्यू साइज बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)